RNI No. DELMUL/2012/47011

26 सितंबर, 2026 शनिवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 177

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com Email : timesofpedia@gmail.com

भारत सरकार के खाते में नहीं जाएगा पैसा : निर्मला सीतारमण 07

भारत में ज्यादा उत्पादन, निवेश, और निर्यात हर सेक्टर में बदलाव साफ दिख रहा

मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर की पोस्ट

नई दिल्ली। मेक इन इंडिया के 12 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इससे भारत के कई सेक्टर्स में बड़ा बदलाव आया है और देश के निर्यात और निवेश में भी इजाफा हुआ है।

एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ज्यादा उत्पादन, निवेश, और ज्यादा निर्यात। हर सेक्टर में बदलाव साफ दिख रहा है। मेक इन इंडिया आने के बाद से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन सात गुना बढ़ गया है, जो 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं, देश में बने डिफेंस उत्पादों की वैल्यू 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन के लिए ग्लोबल हब बनने के मकसद से 25 सितंबर 2014 को ह्यमेक इन इंडियाह्न शुरू किया गया था। आज यह पहल 27 सेक्टर में लागू है, जिनमें 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर शामिल हैं। इस योजना की लागू अवधि में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में मोबाइल-फोन का प्रोडक्शन करीब 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ से बढ़कर 6.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश है।

सरकारी फैक्टशीट के मुताबिक 2024-25 में गाड़ियों का प्रोडक्शन 31.03 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो 2014-15 के मुकाबले 33 फीसदी ज्यादा है। 2020-21 की तुलना में 2024-25 में कई तरह की गाड़ियों के प्रोडक्शन में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वही, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरे और वैल्यू के हिसाब से 11वें नंबर पर है।

2024-25 में सालाना टर्नओवर 4,71,898 करोड़ रुपए तक पहुंच गया मेडिकल डिवाइस की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग 48.2 फीसदी बढ़ी, जो 2019-20 में 28,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 41,500 करोड़ रुपए हो गई है।

गडकरी-सीएम मोहन ने 351 बसें लॉन्च कीं...

21 साल बाद मप्र में सरकारी बस सेवा की वापसी

भोपाल। मध्यप्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा की वापसी हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ किया। दोनों नेताओं ने रिमोट के जरिए 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर सेवा की शुरूआत की। ये बसें प्रदेश के 7 शहरों में इंटरसिटी और इंट्रासिटी सेवाएं देंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई सेवा के तहत 180 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतारी गई हैं। सरकार का उद्देश्य शहरों के साथ गांवों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसके लिए 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बसों में आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों की सुरक्षा और रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले वर्ष में 1,500 बसें संचालित करने का लक्ष्य है। इसके बाद हर साल करीब 2,500 से 3,000 बसें बढ़ाई जाएंगी और वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार बसें संचालित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं, जिससे छोटे गांवों और कस्बों से आवागमन आसान हुआ है। स्कूल-कॉलेज और शहरों तक पहुंच भी सुगम हुई है। उन्होंने कहा कि आज से प्रधानमंत्री ई-बस और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। बस सेवा की शुरूआत कांग्रेस के समय हुई, लेकिन इसे धीरे-धीरे बंद कर दिया गया। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि वे बिना मतलब के ह्हाय रे यारह्न कह रहे हैं। सीएम ने कहा- सरकार जनता के लिए जरूरी कामों को प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने सालभर में 1 लाख पदों पर भर्ती करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो संकल्प लिया था, उसे आज पूरा किया जा रहा है।

गडकरी बोले- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार के विजन का हिस्सा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार के लिए पांच प्रमुख एजेंडे तय किए गए हैं, जिनमें पहला एजेंडा क्लीन ट्रांसपोर्ट यानी स्वच्छ परिवहन है। गडकरी ने कहा कि देश के वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है।

संक्षिप्तवार्ता

कड़े नियम: एनालॉग पनीर को नहीं मिलेगा पनीर का नाम

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दूध, पनीर, मक्खन और मावा जैसे डेयरी उत्पादों की पहचान और लेबलिंग को लेकर नए नियमों का मसौदा जारी किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिलावट या गलत जानकारी से बचाना और उन्हें स्पष्ट बताना है कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं, उसमें वास्तव में कौन-कौन सी सामग्री इस्तेमाल हुई है। बाजार में कुछ इसतरह के उत्पाद मौजूद हैं जो दिखने और इस्तेमाल में बिल्कुल डेयरी उत्पादों जैसे लगते हैं, लेकिन उन्हें बनाने में दूध से प्राप्त सामग्री के बजाय वनस्पति तेल, स्टार्च या अन्य गैर-डेयरी चीजों का उपयोग होता है। इसतरह के उत्पादों को अक्सर एनालॉग पनीर कहा जाता है।

प्रस्तावित नियमों के तहत, इसतरह एनालॉग पनीर या गैर-डेयरी उत्पादों को पनीर जैसे डेयरी नाम से बेचने या उनकी मार्केटिंग करने पर सख्त रोक लगेगी। इसका मतलब है कि वनस्पति तेल, स्टार्च या दूसरी वैकल्पिक सामग्री से बने उत्पादों के नाम, लेबल, पैकेजिंग और विज्ञापन में पनीर शब्द का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका पर आदेश देने से इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार किया, जिसमें हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने और उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार को एक आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाषा से संबंधित सुधार न्यायिक आदेशों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि इस तरह के बदलाव संवैधानिक संशोधन की मांग करते हैं, जो अदालती आदेश से संभव नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देकर तर्क दिया कि अदालत सरकार को ऐसा आयोग बनाने का निर्देश दे सकती है।

320 किमी/घंटा पर बिना झटके ट्रैक बदलेगी बुलेट ट्रेन

आधुनिक कैंटेड टर्नआउट तकनीक का उपयोग हो रहा

नई दिल्ली। भारत की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना में महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, जहां ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी बिना किसी तेज झटके के ट्रैक बदलने में सक्षम होंगी। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक कैंटेड टर्नआउट तकनीक का उपयोग हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को झटके और कंपन से बचाना है। सामान्य रेलवे ट्रैक पर इतनी तेज गति से पटरी से दूसरी पटरी पर जाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ट्रैक की दिशा बदलने पर पहियों और रेल पर अचानक पड़ने वाली ताकत में बदलाव होता है, जिससे तेज झटके महसूस होते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हाई-स्पीड कॉरिडोर में कैंटेड टर्नआउट प्रणाली अपनाई जा रही है। टर्नआउट रेलवे का वह हिस्सा होता है जिसके जरिए ट्रेनें एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाती हैं।

कैंटेड टर्नआउट में घुमावदार ट्रैक पर बाहरी रेल को अंदरूनी रेल से थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, जिसे कैंट या बैंकिंग कहते हैं। यह झुकाव मोड़ पर ट्रेन पर लगने वाली केंद्रीय और अपकेंद्री ताकतों को संतुलित करता है। यह तकनीक टर्नआउट वाले हिस्से में भी इस झुकाव को बनाए रखती है, जिससे ट्रेन अचानक किसी अलग ज्यामिति में प्रवेश नहीं करती। इसके अतिरिक्त, मूवेबल क्रॉसिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सामान्य क्रॉसिंग में जहां दो रेल आपस में मिलती हैं, वहां एक गैप होता है जो तेज गति पर कंपन का कारण बनता है। मूवेबल क्रॉसिंग इस गैप को खत्म करती है, जिससे पहियों का गुजरना सुचारु होता है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉइंट मशीन की भूमिका अहम होती है, जो टर्नआउट के हिस्सों को सही स्थिति में ले जाकर मजबूती से लॉक करती है।

यह उन्नत प्रणाली न केवल यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक आरामदायक बनाएगी, बल्कि ट्रैक बदलते समय लगने वाली अचानक की ताकतों और कंपन में कमी आने से पहियों तथा रेल पर पड़ने वाला दबाव और घिसावट भी कम होगी। इससे लंबे समय में रखरखाव की लागत और जरूरतों को घटाने में मदद मिलेगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलने वाली ट्रेनों के लिए ट्रैक, स्विचिंग सिस्टम और सिग्नलिंग में सटीकता सर्वोच्च प्राथमिकता होती है।

...उम्मीद है

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर कुल 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के हिस्से शामिल हैं। इस परियोजना में पुल, वायाडक्ट, स्टेशन और आठ पहाड़ी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। लक्ष्य है कि परियोजना का पहला खंड, सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर का हिस्सा, दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाए और इस पर 15 अगस्त 2027 तक ट्रेन संचालन शुरू हो सके। पूरी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल लाइन दिसंबर 2029 तक तैयार होने की उम्मीद है।

यूएन में नेपाल ने कहा- मदद के लिए थैंक यू इंडिया

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आपदा के समय भारत की सहायता के लिए विशेष आभार जताया। उन्होंने भोटेकोशी-त्रिशूली आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में भारत और चीन ने नेपाल को तत्काल और उदार सहायता उपलब्ध कराई।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग

नई दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

इसमें निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भी शामिल है, से जुड़े कथित एकतरफा फैसलों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने मतदाता सूचियों से करीब 13 करोड़ नाम हटाए जाने के आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की भी मांग की है।

याचिका में मांग की गई है कि यदि अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना कोई फैसला लिया गया है तो उसे अवैध घोषित किया जाए। इसके अलावा मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल फॉर्म-6 को बहाल करने की मांग भी की गई है। याचिका में सीईसी ज्ञानेश कुमार, उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और ईसीआई की आईटी प्रमुख सीमा खन्ना के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

यह याचिका उस रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और बहाल करने तथा मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी।

हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि एसआईआर समेत पिछले एक वर्ष में लिए गए सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी इसमें शामिल रही है। आयोग ने यह भी कहा कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग सुझाव और टिप्पणियां निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं।

यूपीआई एमडीआर: 2000 हजार से अधिक की खरीद पर दुकानदारों को चुकाना होगा शुल्क

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) का खर्च ग्राहक नहीं, बल्कि दुकानदार या व्यापारी उठाएंगे। देश में इसबारे में चल रही अटकलों और चिंताओं को दूर करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि एमडीआर कोई कर, सेस या सरचार्ज नहीं है, बल्कि यह एक शुल्क है जो सीधे सरकार के

खजाने में नहीं आता है। उन्होंने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि उन्हें इस शुल्क को लेकर चिंतित होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि यह सीधे उन पर लागू नहीं होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जिस तरह पहले क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर लगता था, लेकिन उसका शुल्क ग्राहक नहीं बल्कि दुकानदार उठाते थे, ठीक उसी तरह यूपीआई के मामले में भी यह शुल्क व्यापारियों द्वारा वहन होगा। नए फ्रेमवर्क के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन पर, 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.40 प्रतिशत तक का एमडीआर लगेगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की है, जिसका अर्थ है कि इससे अधिक एमडीआर नहीं वसूला जाएगा। इसके विपरीत, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान (पी2पी) पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और उस पर कोई एमडीआर लागू नहीं होगा।

मध्य प्रदेश में मिले 70 फर्जी पासपोर्ट, एसटीएफ ने 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार

भोपाल। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने संगठित फर्जी पासपोर्ट रैकेट की जांच में करीब 70 फर्जी पासपोर्ट का पता लगाया है। ये पासपोर्ट राज्य में अलग-अलग पतों का इस्तेमाल करके बनवाए गए थे। अब जांच में बड़े नेटवर्क और अधिकारियों की मिलीभगत की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसटीएफ के डीआईजी ने शुक्रवार को बताया कि अब तक छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और फर्जी पासपोर्ट बनाने और हासिल करने के पीछे पूरे नेटवर्क का पता लगाने की जांच जारी है। डीआईजी ने कहा कि यह एक बहुस्तरीय मामला है और जांच अभी भी चल रही है। अब तक छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो दिन पहले की गई ताजा गिरफ्तारी भी शामिल हैं। 23 सितंबर को गयाप्रसाद गौतम को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच रियाल चौधरी उर्फ भंते मेतानंद, विप्लब अधिकारी, प्रियन रॉय, जॉय चौधरी और नसीम अख्तर को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ के मुताबिक जांच में सामने आया है कि पासपोर्ट आवेदनों में बौद्ध मठों के पतों का बार-बार इस्तेमाल किया गया।

तट पार कर चुका चक्रवात अर्नब, फिर भी आफत बरकरार, भारी बारिश का अनुमान

वेब वार्ता, नई दिल्ली

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव (डीप डिप्रेशन) आखिरकार उत्तरी आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के पास तट को पार कर चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, यह सिस्टम 23-24 सितंबर की दरम्यानी रात में तट से टकराया। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में इस चक्रवात अर्नब नाम दिया था, लेकिन आईएमडी ने अपने आधिकारिक बयान में डीप डिप्रेशन के रूप में ही दर्ज किया है, जिसका अर्थ है कि यह तकनीकी रूप से चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक नहीं पहुंचा था। तट पार करने के बाद यह सिस्टम अब धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसका असर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है।

आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में यह सिस्टम पहले एक निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ, फिर डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन में बदल गया। तट पार करते समय, इसके साथ 55 से 65

किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, और झोंकों की रफ्तार करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची थी। 24 सितंबर की सुबह तक यह कलिंगपट्टनम से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में जमीन के ऊपर आगे बढ़ रहा था।

...और हल्की बारिश देखी जा सकती है

पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और गांगेय हिस्सों में भी 25 सितंबर को बहुत भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की आशंका है, जिसका असर कोलकाता समेत कई शहरों पर पड़ सकता है। डीप डिप्रेशन के जमीन के ऊपर बढ़ने से इसका प्रभाव पूर्वी और मध्य भारत के हिस्सों तक पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, झारखंड और मध्य प्रदेश के खासकर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मौसम में बदलाव और हल्की बारिश देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने बताया है कि सिस्टम के कमजोर होने का मतलब यह कतई नहीं है कि बारिश का खतरा तुरंत टल गया है; बल्कि इसके पीछे मौजूद नमी और वायुमंडलीय परिस्थितियां कई राज्यों में तीव्र वर्षा का कारण बन सकती हैं। इस मौसम प्रणाली का सबसे व्यापक और गंभीर असर ओडिशा पर देखने को मिल रहा है। आईएमडी ने 25 और 26 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जाहिर किया है। एहतियात के तौर पर पुरी सहित कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद किए गए हैं, और समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और लोकल स्तर पर बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा है।

संपादकीय

ज्ञानेश का चुनाव आयोग !

भारत के चुनाव आयोग के भीतर की असहमतियां सामान्य नहीं हैं। वे राजनीतिक भी नहीं हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेताओं के आरोप भी नहीं हैं। याद रखना चाहिए कि चुनाव आयोग कोई एक व्यक्ति नहीं, बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है। यह व्यवस्था और दर्जा संसद में पारित किया गया है। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार ने चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय कर उसे अधिनायकवाद से बचाया था। तब की कांग्रेस सरकार तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) टीएन शेषन से बहुत दुखी और परेशान थी, नतीजतन आयोग में तीन आयुक्तों की व्यवस्था की गई। सीईसी और दो अन्य आयुक्तों की संवैधानिक शक्तियां एक समान तय की गईं। अलबत्ता सीईसी बैठकों की अध्यक्षता जरूर कर सकते हैं, यह भी तय किया गया। कोई भी फैसला, आदेश, निर्देश चुनाव आयोग का तब मान्य और स्वीकार्य होगा, जब आयुक्त सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय लेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खोजी खबर और विश्लेषण के बाद चुनाव आयोग का भीतरी यथार्थ और विरोधाभास सार्वजनिक हुए हैं कि 10 महीने में 14 आपत्तियां दो चुनाव आयुक्तों–सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी–ने जताई हैं। उनमें से कुछ सीईसी को भी भेजी गई हैं। ये सामान्य आपत्तियां नहीं हैं। संवैधानिक शख्स की आवाज हैं। वैचारिक मतभेद और बहुसदस्यीय आयोग होने के कारण अथवा किसी भी विविध मंच पर ऐसी असहमतियां जताना बुनियादी तौर पर लोकतांत्रिक है। सवाल है कि चुनाव आयोग का भीतरी मामला कैबिनेट सचिव तक पहुंचने की नौबत क्यों आई? दोनों असहमत आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठियां लिख कर शिकायत क्यों दर्ज कराई? चुनाव आयोग भारत सरकार के तहत काम नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति ही सीईसी सहित तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, बेशक भारत सरकार की सलाह पर ही नियुक्तियां की जाती हैं। असहमत आयुक्तों को सीधा राष्ट्रपति को पत्र लिख कर शिकायत करनी चाहिए थी। क्या ऐसे संदर्भ के बावजूद आयोग दावा कर सकता है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं? दूसरा मामला फॉर्म 6 का चुनाव आयुक्तों ने उठाया है।

यह संविधान और सरकारी कार्यप्रणाली का घोर उल्लंघन भी है, यदि फॉर्म में बदलाव किए गए हैं! दोनों असहमत चुनाव आयुक्तों ने फॉर्म 6 में कथित बदलाव को अवैध और अनधिकृत करार दिया है। आयोग को ऐसे संशोधन या परिवर्तन करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। बदलाव का विशेषाधिकार सरकार और संसद को है। कानून मंत्रालय का विधायी विभाग अपेक्षित बदलाव के बाद गजट में अधिसूचना जारी करता है। उसके बाद ही चुनाव आयोग किसी बदलाव को लागू और प्रभावी कर सकता है। इसके अलावा, दोनों असहमत चुनाव आयुक्तों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), काटे गए करीब 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम, मतदाता सूचियों के केंद्रीकरण, आईटी विभाग की डीजी सीमा खन्ना, मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की संबद्ध विभाग तक पहुंच न होने, संपूर्ण आयोग के फैसले या निर्देश के बिना ही आधिकारिक बयान जारी करने और अधिकारियों की विदेश यात्रा, बैठकों के एजेंडे और मिनट्स उपलब्ध न कराए जाने पर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इसके साफ मायने हैं कि आयोग में सीईसी का अधिनायकवाद और एकाधिकार जारी रहा है। फैसले सीईसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के स्तर पर ही लिए जाते रहे हैं। मतदाता सूचियों के केंद्रीकरण का मतलब यह है कि आयोग के स्तर पर किसी भी मतदाता का नाम जोड़ा या काटा जा सकता है। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा में हम ऐसा महसूस कर चुके हैं। बंगाल में ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं और अभी तक 91 फीसदी से अधिक मतदाताओं को बहाल किया जा चुका है। उनके नाम सूची में शामिल करने के विरोध की भी अपील की गई है। उसमें भी चुनाव आयोग की भूमिका सामने आई है, क्योंकि असहमत आयुक्तों ने सवाल उठाए हैं। बहरहाल आश्चर्य यह है कि अखबार की सांगोपांग खबर को न तो तीनों आयुक्तों में से किसी ने भी खारिज किया है और न ही तीनों ने एक साथ सार्वजनिक मंच पर आकर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग के उपनिदेशक की सफाई सरकारी किस्म की, बेमानी है। विपक्ष और देश के निशाने पर सीईसी हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का ही है? विपक्ष उनके खिलाफ केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर रहा है। देश के युवा भी कई सवाल कर रहे हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय

चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्ति की अनदेखी का मतलब है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया का नाम नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती इस बात से तय होती है कि चुनाव कितने पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से कराए जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर उठने वाली किसी भी असहमति को महज प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की ओर से बार-बार यानी १४ बार लिखित आपत्ति दर्ज किए जाने की खबर ने इसी कारण गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिज्ञों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि इसका हल कैसे निकाले? वहीं ऐसी बातों से मतदाताओं के बीच भी लोकतंत्र की इस संवैधानिक संस्था के प्रति सोचना पड़ता है। यह ऐसे संस्था है कि जहां कुछ भी हो तुरंत प्रभावी कार्य हो जिससे पारदर्शिता सबके सामने आये।

देश के प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब दस महीनों में आयोग के विभिन्न फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। बताया गया है कि इन आपत्तियों का संबंध केवल तकनीकी या प्रक्रियागत विषयों तक सीमित नहीं था, बल्कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता डेटा के केंद्रीकरण तथा चुनावी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तक अधिकारियों की पहुंच जैसे संवेदनशील मुद्दों से था। यहां मूल चिंता यह नहीं है कि किसी संवैधानिक संस्था में अलग-अलग राय क्यों सामने आई। लोकतांत्रिक संस्थाओं में असहमति अपने आप में कोई कमजोरी नहीं है। बल्कि स्वस्थ संस्थागत व्यवस्था में अलग राय रखना और उसे रिकॉर्ड पर दर्ज करना एक आवश्यक प्रक्रिया मानी जाती है। चिंता तब पैदा होती है जब यह सवाल उठे कि क्या उन आपत्तियों पर पर्याप्त विचार किया गया और क्या निर्णय प्रक्रिया वास्तव में सभी संबंधित सदस्यों की भागीदारी से आगे बढ़ी?

चुनाव आयोग तीन सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इसके सदस्य हैं। यदि दो सदस्यों की ओर से महत्वपूर्ण मामलों में बार-बार लिखित आपत्तियां दर्ज की गई हैं, तो इन आपत्तियों की प्रकृति, उनका निस्तारण और अंतिम निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया सार्वजनिक विमर्श का विषय बनना स्वाभाविक है। विशेष रूप से मतदाता सूची का मामला अत्यंत संवेदनशील है। मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होती। यही वह आधार है जो तय करती है कि चुनाव के दिन कौन नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए मतदाता सूची में किसी नाम का जुड़ना, हटना या बहाल होना सीधे तौर पर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा प्रश्न है।

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर सामने आई आपत्ति इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। फॉर्म-6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वैधानिक फॉर्म है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इसमें ऐसा घोषणा-पत्र जोड़ा गया, जिसमें आवेदक से यह बताने को कहा गया कि उसका या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली मतदाता सूची में था या नहीं। यदि किसी प्रक्रिया में इस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा हो और उससे पहले आयोग के ही दो सदस्यों की आपत्ति सामने आई हो, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि उस आपत्ति पर क्या विचार हुआ और बदलाव का अंतिम आधार क्या था।

मामला केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर के निर्वाचन अधिकारियों की मतदाता डेटा से जुड़े फैसलों को सिस्टम में दर्ज करने की क्षमता प्रभावित हुई। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे मामलों का भी उल्लेख है, जहां दस्तावेजों की जांच के बाद लोग पात्र पाए गए, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर तकनीकी बाधाएं सामने आईं। गोवा में 97 पात्र मतदाताओं का मामला भी इसी तरह की तकनीकी समस्या से जुड़ा बताया गया है।

यह स्थिति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि चुनावी प्रक्रिया में अंतिम निर्णय किसका होगा, मैदानी स्तर पर काम कर रहा निर्वाचन अधिकारी या केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम? तकनीक चुनावी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन वह लोकतांत्रिक निर्णय का विकल्प नहीं बन सकती। किसी तकनीकी प्रणाली में हुई त्रुटि के कारण यदि पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता, तो इसका सीधा असर उसके मताधिकार पर पड़ सकता है। हालांकि, इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में बताए गए कथित आंतरिक मतभेद के निष्कर्ष को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि सदस्यों की ओर से नोटिंग, टिप्पणियां, सुझाव और अलग-अलग राय देना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसले लिए जाते हैं और एसआईआर सहित महत्वपूर्ण निर्णय तीनों आयुक्तों की मंजूरी से हुए हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि लिखित आपत्तियां अपने आप में आयोग के भीतर किसी निर्णायक विभाजन का प्रमाण हैं। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि ऐसी आपत्तियों को पूरी तरह सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी कहकर सार्वजनिक चिंता को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज हुई हैं, तो लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मांग यही होगी कि कम से कम यह स्पष्ट किया जाए कि किन मुद्दों पर असहमति थी, उन पर क्या विचार हुआ और अंतिम निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिया गया।

विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है, जबकि राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और विशेष गहन पुनरीक्षण रोकने की मांग उठाई है। राहुल गांधी ने भी मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान से जोड़ा है। इन राजनीतिक दावों की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसलिए इनका मूल्यांकन स्वतंत्र तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। असल चुनौती किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि चुनावी संस्थाओं पर जनता के भरोसे की है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियादी पूंजी है। इसलिए आयोग के भीतर असहमति सामने आए तो उसका समाधान अधिक पारदर्शिता, स्पष्ट जवाबदेही और सार्वजनिक स्पष्टीकरण से होना चाहिए, न कि केवल विवाद को खारिज कर देने से।

जरूरत इस बात की है कि मतदाता सूची से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बदलावों का स्पष्ट ऑडिट ट्रेल उपलब्ध हो। किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया, किस आधार पर लिया, किस स्तर पर उसे बदला गया और तकनीकी प्रणाली ने उस निर्णय को कैसे दर्ज किया। इन सवालों के जवाब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अस्पष्ट नहीं रहने चाहिए। साथ ही, आयोग के भीतर दर्ज असहमति और उसके निस्तारण की संस्थागत प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए।

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव तभी बन सकता है, जब हर पात्र नागरिक को यह भरोसा हो कि उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित है और चुनावी प्रक्रिया किसी अदृश्य तकनीकी या प्रशासनिक हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होगी। चुनाव आयोग के दो सदस्यों की 14 लिखित आपत्तियों का मामला इसी भरोसे की कसौटी है। असहमति लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती; असहमति को सुनने और उसका पारदर्शी समाधान न करने की व्यवस्था जरूर लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है।

सौरभ वार्ष्णेय

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

टीएमसी के 20 बागी सांसद, तारीख पर तारीख का खेल ?

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षा जताई है, जल्द से जल्द इस मामले में स्पीकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा तय नहीं की। यह जरूर कहा, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश नहीं दे सकती है। जल्द से जल्द मामला निपटाने की याद जरूर दिला सकती है। ऐसी याद दिलाने का कोई असर नहीं होता है। जब भय ही नहीं होगा, तो इस तरह के निर्देश का कभी पालन भी नहीं होगा। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नोटिस के बावजूद भी सांसदों ने कोई जवाब नहीं दिया। सलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष नोटिस जारी कर चुके हैं। वहीं बाकी सांसदों कि ओर से पेश वकीलों ने कहा, वह चार सप्ताह के अंदर नोटिस का जवाब दाखिल कर देंगे। कुल मिलाकर तारीख पर तारीख का यह खेल कोई नई बात नहीं है। दल-बदल कानून के अंतर्गत दल बदलने वाले सांसदों और विधायकों की अयोग्यता को लेकर महाराष्ट्र से जो खेल शुरू हुआ था, सारे देश ने उसका हश्र देख लिया है। महाराष्ट्र के मामले में भी इसी तरह से तारीख पर तारीख का खेल चला था। विधानसभा अध्यक्ष ने कई महीनों तक फाइल को अपने पास दबा के रखा था। इसी बीच चुनाव आयोग भी एक-दूसरे की मदद कर रहे थे। चुनाव आयोग, सुप्रीमकोर्ट और विधानसभा/ लोकसभा अध्यक्ष के बीच में इसी तरह का खेल कई बार पहले भी खेला जा चुका है। समय निकलने के बाद इस तरह की याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह फैसला इसी तरह का हुआ, जब आदमी मर गया, तब उसके मामले में फैसला आया। उसके मरने के कारण फाइल बंद कर दी गई? लेकिन उसे समय पर न्याय नहीं मिला। महाराष्ट्र की लंबित दल-बदल याचिकाओं पर कानूनी बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यह धारणा बनती चली जा रही है। दलबदल जैसे संवेदनशील मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विवाद और दबाव से बचने के लिए तारीख पर तारीख का खेल खेलते हैं। विशेष रूप से उन मामलों में जहां लाभान्वित पक्ष भाजपा हो। तेलंगाना में एक विधायक के दलबदल मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने फटाफट फैसला सुना दिया है। विधायक की सदस्यता निरस्त कर दी है। वहीं पिछले 4 महीने से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के यहां जो याचिका दायर कर कार्यवाही की मांग की थी। मानसून सत्र भी निकल गया। लोकसभा अध्यक्ष के यहां से तारीख पर तारीख का खेल खेला जा रहा है। इससे व्यथित होकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख पर तारीख का खेल खेलना शुरू कर दिया है।

फैसला कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल भी इस मामले में सरकार की ओर से खड़े होकर बागी सांसदों और विधायकों की मदद कर रहे हैं। दल-बदल कानून को लेकर पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी जब कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, दलबदलू वहां विधायक और मंत्री बने रहे। दोबारा चुनाव लड़ लिया। फैसला अभी तक नहीं आया। रही सही कसर चुनाव आयोग ने पूरी कर दी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शिवसेना का चुनाव चिन्ह सीज करके नया चुनाव चिन्ह दे दिया। कुछ इसी तरह की कार्यवाही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में की है। जिसके कारण देश में संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जो विश्वास आमजनों के मन में था, वह विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब यह धारणा बनने लगी है, न्यायपालिका सहित अन्य संवैधानिक संस्था जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। सब सत्तारुड दल भाजपा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, या तो मामले को टालते हैं या ऐसा निर्णय देते हैं, जिससे क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राकपा के साथ यही हुआ। अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ यही सब हो रहा है। आम आदमी और राजनीतिक दल इस खेल को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। जिसके कारण सड़कों पर आकर विरोध करना और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बन रहा है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सभी संवैधानिक संस्थाओं और सभी सरकारों के कार्यों की समीक्षा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के अनुसार यदि समय पर सुनवाई नहीं करती हैं या समय पर निर्णय नहीं करती हैं। जबकि उन्हें समीक्षा करने के बाद आदेश देने का पूर्ण अधिकार है। पिछले कुछ वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं के साथ-साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तारीख पर तारीख का खेल खेला जा रहा है। अंतिम फैसला करने के स्थान पर अंतरिम आदेश देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसका फायदा त्वरित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है। पीड़ित पक्ष इंतजार करता रह जाता है। संवैधानिक संस्थाओं की यह ट्रिक साँप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इस हालत को देखते हुए अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग में जो विद्रोह देखने को मिल रहा है, वह इसी का परिणाम है। यदि समय रहते न्याय नहीं होगा, तो देश में अराजकता की स्थिति निर्मित होगी। लोकतंत्र कमजोर होगा। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट जब अपने आपको असमर्थ और कमजोर मानने लगेगी, ऐसी स्थिति में अराजकता की स्थिति ही उत्पन्न होगी। संविधान ने न्याय पालिका को सर्वोच्च स्थान दिया है। उसकी समीक्षा के दायरे में सभी हैं।

(लेखक – सनत जैन)

विद्यार्थियों की संख्या सवा तीन करोड़ घटी

सरकारी स्कूलों में भी अध्यापकों की भर्ती में काफी ढील वाला माहौल है और 33 फीसदी कमी की रिपोर्ट इसमें है। मजेदार सूचना यह है कि इस मामले में निजी स्कूलों का रिकार्ड सरकार से बेहतर है। इसके साथ ही यह भी हुआ है कि शहरी प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मुकाबले बेहतर वेतन मिलता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों को वेतन कम मिलता है।

हैरान करने वाली बात है कि देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर एक नामी और विश्वसनीय संस्था के सर्वेक्षण से निकले निष्कर्षों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। खबर के रूप में कहीं-कहीं यह बात आई कि टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंस की रिपोर्ट 'स्टेट आफ टीचर्स, टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन इन इंडिया' नामक रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से बच्चों की संख्या में तीन साल में ही सवा तीन करोड़ की कमी आ गई है। 2021-22 में यह संख्या 26.5 करोड़ थी जो 2024-25 में घटकर 23.2 करोड़ रह गई है। शिक्षा अधिकार कानून और विकलांग लोगों के अधिकार कानून को लागू करने के बाद विद्यार्थियों की संख्या में बहुत तेज वृद्धि हुई थी और इन कानूनों के विरोधी कहते थे कि यह भीड़ सिर्फ खिचड़ी खाने वाले बच्चों की है, पढ़ने वालों की नहीं। 'टीस' के इस सर्वेक्षण में इस तरह की मान्यता से शुरूआत नहीं हुई है लेकिन कुछ आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि पढ़ाई का स्तर गिरा है और बच्चों के सीखने के बुनियादी स्तर में गिरावट आई है। शिक्षा के स्थिति संबंधी दो एनी सर्वेक्षणों से यह नतीजा आया है कि बच्चों के ज्ञान के स्तर के साथ सीखने के क्षमता में भी कमी आई है।

इस रिपोर्ट की खूबी यह है कि इसने इस गिरावट को गरीब और फटेहाल बच्चों के स्कूल पहुंचने की परिघटना के रूप में न बताकर शिक्षकों की कमी और उनके भी ज्ञान में कमी से भी जोड़ा है। यह सर्वेक्षण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा और मिजोरम में किया गया और यह नतीजा निकाला कि स्कूलों में गणित और विज्ञान के अध्यापकों की भारी कमी है। जो लोग गणित पढ़ा भी रहे हैं उनमें से पचास फीसदी ने ही हाई स्कूल में भी गणित की पढ़ाई की थी। अंग्रेजी और भाषा पढ़ाने वालों का हाल इससे बेहतर है लेकिन वह भी 30 फीसदी की कमी वाला इलाका हैं। सरकारी स्कूलों में भी अध्यापकों की भर्ती में काफी ढील वाला माहौल है और 33 फीसदी कमी की रिपोर्ट इसमें है। मजेदार सूचना यह है कि इस मामले में निजी स्कूलों का रिकार्ड सरकार से बेहतर है। इसके साथ ही यह भी हुआ है कि शहरी प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के मुकाबले बेहतर वेतन मिलता है लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों को वेतन कम मिलता है।

एक अन्य रिपोर्ट भी इसी प्रवृत्ति को बताती है जो पंजाब के स्कूलों को लेकर किया गया था। वहां की मुख्य शिकायत तो यही रही कि सरकारी स्कूल दलित स्कूल में बदल गए हैं क्योंकि बाकी लोग अपने बच्चों को निजी और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजते हैं। ऐसे स्कूल अब गांव-गांव में खुल गए हैं। यह बदलाव दिल्ली से लेकर बिहार तक में देखा जा सकता है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में अच्छे भवन हैं, शिक्षक हैं, पढ़ने के बाकी साधन हैं लेकिन समाज के ऊंचे तबके के बच्चे नदारद हैं। बिहार के देहात तक में पहुंचे प्राइवेट स्कूल, जो असल में बेरोजगार और पढ़े-लिखे लड़के-लड़कियों के बल पर ही चलते हैं। अब हास्टल और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कराके दूर-दूर से बच्चे जुटाने लगे हैं। 'टीस' वाली रिपोर्ट में छात्रों की संख्या की गिरावट को रेखांकित करने के साथ यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 लागू होने के बाद से शिक्षकों की संख्या में छह लाख की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में छात्रों की संख्या गिरना ज्यादा चिंता की बात है।

रिपोर्ट में एक दूसरी धनात्मक प्रवृत्ति को भी रेखांकित किया गया है कि अध्यापकों में महिला शिक्षिकाओं का हिस्सा तेजी से बढ़ा है। अब यह 54 फीसदी तक पहुंच गया है जो भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए पर इसमें एक कमी है। यह वृद्धि शहरी ज्यादा है ग्रामीण कम। शहरी शिक्षकों में महिलाओं का हिस्सा जहां 67 फीसदी है वहीं ग्रामीण इलाकों में उनका अनुपात 47 फीसदी है। यह चिंता की खास बात नहीं है लेकिन रिपोर्ट में एक कक्षा में कई-कई वर्ग के विद्यार्थियों को साथ पढ़ाने का मर्ज बढ़ता गया है। पहले वाले सर्वेक्षण में ऐसा 39 फीसदी कक्षाओं के साथ था तो अब यह बढ़कर लगभग आधा हो गया है। यह अनुपात सरकारी स्कूलों का है। बल्कि कई स्कूल तो अकेले मास्टर के बल पर चल रहे हैं। संसाधनों के प्रबंधन और विद्यार्थियों की कमी के नाम पर उनको बंद करने की परिघटना अलग चिंता का विषय है। बंद होने वाले स्कूलों के मामले में उत्तर प्रदेश चैंपियन है। ऐसा दिल्ली में भी हुआ है जहां लंबे समय तक शासन करने वाले आप के लोग सरकारी स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देने का दावा करते रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए अनहोम ने जरूर काफी प्रयास किया लेकिन उनके शासन में भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटी। शिक्षा के अंदर के बदलावों के साथ यह भी अच्छा हुआ है कि शिक्षा का मामला चुनावी मुद्दा बन रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों का बड़े पैमाने पर बंद होना मुद्दा बन गया है। दिल्ली में यह लगातार एक मुद्दा रहा है। ऐसे में इस रिपोर्ट के नतीजों पर चर्चा न होना हैरान करता है।

लेखक – अरविन्द मोहन

आलेख

भारतीय कूटनीति का नया क्षितिज : ब्रिक्स सम्मेलन

इस सम्मेलन की सफलता का प्रतिफलन यह है कि व्यापारिक नवोन्मेष और वित्तीय संप्रभुता के साथ आर्थिक और व्यापारिक मोर्चों पर भारत ने व्यापारिक लेन-देन में दूसरे देशों की मुद्रा पर निर्भरता कम करने की बात पर बल दिया है।

ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को और मजबूत करने के साथ, देश से बाहर डिजिटल भुगतान प्रणालियों के आपसी जुड़ाव और वैश्विक ऊर्जा एवं आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने जैसे मुद्दों पर आपसी बातचीत से एक ऐतिहासिक सहमति बनती दिख रही है।

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा'-जिस प्रकार मोरों में कलगी और नागों में मणि का स्थान सर्वोपरि है, ठीक उसी प्रकार समकालीन राजनीति के इस दौर में आज का भारत वैश्विक कूटनीतिक धरातल पर अपनी समभाव की भावना को आगे बढ़ाने में सर्वोपरि रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भव्य 'भारत मंडपम' में संपन्न हुआ 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन महज अंतरराष्ट्रीय देशों की मेजबानी करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह बदलते राजनैतिक परिदृश्य में भारत की कूटनीतिक दूरदर्शिता और वैचारिक नेतृत्व के एक नए क्षितिज का निर्माण भी कर रहा था। पारस्परिक लचीलापन, सकारात्मक नवाचार, आपसी सहयोग आदि मूलमंत्र के साथ, 'नई दिल्ली घोषणापत्र' पर सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति को कूटनीति के क्षेत्र में भारत की एक अद्वितीय और निर्णायक पहल के रूप में देखा जा सकता है। आज के दोहरे वैश्विक संकटों, जिनमें पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान का युद्ध और पूर्वी यूरोप में रूस-यूक्रेन संघर्ष प्रमुख हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस शिखर सम्मेलन में इन संकटों के बीच एक साझा आम सहमति बनाने की कोशिश वैश्विक पटल पर शांति के क्षेत्र में नई संजीवनी की तरह काम करेगी। जिससे वैश्विक पटल पर शांति के नए द्वार खोले जा सकते हैं।

इस सम्मेलन समूचे नीतिगत ढांचे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत मंडपम केवल वैश्विक देशों के भाषणों का मंच ही नहीं बनकर रह गया, बल्कि वह ब्रिक्स देशों के आपसी संबंधों का नया ताना-बाना तैयार करने के साथ, इन संबंधों को सुधारने और द्विपक्षीय विमर्श को एक नई दिशा-दशा तय करने वाली प्रयोगशाला भी बनाकर उभरा। सीमाई गतिरोधों को दूर करने और पूर्व-स्थापित समझौतों का सम्मान करने की पृष्ठभूमि में भारत और चीन के बीच हुई गंभीर बातचीत ने यह दशार्या है कि कूटनीतिक परिपक्वता के आलोक में आपसी संबंधों के बीच घिर आए बादलों से उपजे अंधेरे को दूर किया जा सकता है।

आज अमेरिकी प्रतिबंधों से अनेक देश प्रभावित हैं। भारत इससे अछूता नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इन प्रभावित देशों के साथ भारत का सकारात्मक संवाद आपस के आपसी समन्वय की गति को बढ़ाने वाला साबित होगा। इस संवाद को कूटनीतिक स्वायत्तता की नई मिसाल की तरह देखा जा रहा है। वहीं, ब्रिक्स के नए सदस्य देशों के साथ भारत ने अपने पारंपरिक ऊर्जा संबंधों में सुधार करते हुए एक नए मैत्रीपूर्ण सेतु को तैयार करने का महत्वपूर्ण काम किया है।

इस सम्मेलन की सफलता का प्रतिफलन यह है कि व्यापारिक नवोन्मेष और वित्तीय संप्रभुता के साथ आर्थिक और व्यापारिक मोर्चों पर भारत ने व्यापारिक लेन-देन में दूसरे देशों की मुद्रा पर निर्भरता कम करने की बात पर बल दिया है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को और मजबूत करने के साथ, देश से बाहर डिजिटल भुगतान प्रणालियों के आपसी जुड़ाव और वैश्विक ऊर्जा एवं आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने जैसे मुद्दों पर आपसी बातचीत से एक ऐतिहासिक सहमति बनती दिख रही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह सम्मेलन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामरिक, भौगोलिक और साहित्यिक जैसे अनेक क्षेत्रों के बीच पनप रही चेतना के अद्भुत संगम की तरह हमारे सामने खड़ा अपनी सफलता का जश्न मना रहा है। इसी के फलस्वरूप इस सम्मेलन में मानवीय सरोकारों के स्तर पर, भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज' और महामारी से निपटने के लिए एक त्वरित वैक्सीन सहयोग नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखकर महत्वपूर्ण पहल की है। ऐसे में हम यदि सांस्कृतिक और साहित्यिक के रूप में इस सम्मेलन की बात करें तो लंबे समय से वैश्विक अकादमिक विमर्श और राजनैतिक-ऐतिहासिक आख्यानों पर पश्चिमी जगत का एकाधिकार रहा है।

भारत ने न केवल इस एकाधिकार के बरक्स सदस्य देशों के विचारकों, इतिहासकारों और साहित्यकारों को एक मंच प्रदान किया, बल्कि खुद भी इस एकाधिकार का हमेशा से विरोध करता चला आ रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्व और विकासशील देशों के अपने समृद्ध दर्शन, मत, वैचारिक सरोकार और समकालीन सामाजिक-साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को वैश्विक मुख्यधारा में उनका सही व सम्मानजनक स्थान दिलाना था। इस ब्रिक्स सम्मेलन से यह संदेश संप्रेषित हुआ कि से सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से भारत एक मजबूत सहयोगी की तरह सबके साथ खड़ा है। क्योंकि इस सम्मेलन ने केवल वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि भविष्य की नई संभावनाओं की तरफ भी सबका ध्यान खींचा। ब्रिक्स देशों के इस मंच से भविष्य की नई संभावनाओं के साथ एक न्यायसंगत मंच का एकजुटता दिखाते हुए शक्ति की मौलिक संकल्पना के साथ उभरना एक ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। इस मंच से एक वैकल्पिक वैश्विक शासन का ऐसा ढांचा बनाने में मदद मिली। जिसके फलस्वरूप आपसी सहयोग के मजबूत होने से भविष्य में एक ऐसा लोकतांत्रिक ढांचा तैयार हो रहा है, जो पश्चिमी देशों के एक तरफा प्रतिबंधों और संरक्षणवाद के खिलाफ विकासशील देशों को एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा साथ ही ब्रिक्स देशों ने इस मंच पर 'मिशन लाइफ' और जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों को अपनाकर भविष्य में हरित ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूलन जैसे नवाचारों के लिए नए निवेश और संयुक्त अनुसंधान के नए द्वार खोलने का महती काम किया है। ब्रिक्स 2026 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लोकतंत्रीकरण की राह में चलने का आह्वान किया। इसकी सहायता से आने वाले समय में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ने और वैश्विक व्यापार में किसी एक मुद्रा के वर्चस्व से मुक्त होकर संतुलित और समावेशी रास्ता अपनाने पर जोर दिया।

इस सम्मेलन के समूचे पहलुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत आज उस वैश्विक मुकाम पर अवस्थित है, जहां उसकी शांतिप्रियता कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अटूट आर्थिक-सामरिक शक्ति और कूटनीतिक सामर्थ्य का परिचायक है। ऐसे में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की यह प्रसिद्ध पंक्तियां आज के सशक्त, समन्वयक और मध्यस्थ भारत की कूटनीतिक स्थिति पर सटीक बैठती प्रतीत होती हैं-'क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो/ उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो।'

दो दिन चले इस मंथन में भारत ने अपनी चाणक्य सरीखी नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि ब्रिक्स किसी एक विचारधारा या देश के प्रभुत्व में न आकर, वह वैश्विक कल्याण की भावना, नवीन नवाचार और सतत विकास के लिए एक व्यावहारिक और सहयोगी मंच के रूप में सबके साथ खड़ा रहे। इस सम्मेलन के माध्यम से 'भारत मंडपम' से निकला मैत्री का यह उद्घोष आने वाले दशकों तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र, सामरिक दृष्टि, संस्कृति और वैश्विक चिंतन की दशा-दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगा। अदम गोंडवी से माफी मांगते हुए उनके शब्दों में कुछ बदलाव के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि-

जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, भारत की कूटनीति मुस्कुराई मंडपम के हाल में।

डॉ.नीरज कुमार मिश्र

संक्षिप्त वार्ता

सत्य निकेतन हादसा मामले में अब अदालत की मदद करेंगी किरण बेदी

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। सत्य निकेतन में इमारत गिरने के कारण छात्रों सहित नौ लोगों की मौत के मामले में अदालत की मदद करने के अनुरोध से जुड़ी पूर्व आइपीएस व पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें किरण बेदी के अदालत की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस संबंध में कोई आदेश न दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसजी के तर्क को सुनने के बाद कहा कि अदालत किरण बेदी को अदालत में अपनी बात रखने की अनुमति देती है। पीठ ने कहा कि हम पक्षों को यह भी निर्देश देते हैं कि इस मामले में कोई भी दस्तावेज या दलीलें दायर करते समय, उनकी एक प्रति किरण बेदी को भी दी जाए। उक्त निर्देश के साथ अदालत ने किरण बेदी की अर्जी का निस्तारण कर दिया।

तीन साल बाद फिर गठित हुआ दिल्ली बाल आयोग

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का तीन साल बाद पुनर्गठन हुआ है। आयोग की ओर से 24 सितंबर को कश्मीरी गेट स्थित अंतरराज्यीय बस अड्डे पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण से जुड़ी पहलों की जानकारी दी गई। आयोग की अध्यक्ष स्वाति गुप्ता और अन्य सदस्यों ने बताया कि बच्चों की देखभाल के लिए आफ्टर केयर व्यवस्था को आदर्श राज्य मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके तहत बाल गृहों से बाहर आने वाले बच्चों को विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़कर उनके बेहतर भविष्य के लिए अवसर उपलब्ध कराने की योजना है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता युवा कांग्रेस कार्यालय से चुनाव आयोग की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। आयोग के कामकाज पर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सीईसी से इस्तीफा देकर आरोपों की जांच का सामना करने की मांग की। युवा कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। संगठन ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने तरूण तेजपाल मामले में दो नोटिस जारी किए

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल की सजा से जुड़े दो नोटिस जारी किए। पहला नोटिस गोवा पुलिस को पत्रकार की उस याचिका पर दिया गया जिसमें उन्होंने अपनी 10 साल की सजा को चुनौती दी है। दूसरा नोटिस तेजपाल को गोवा सरकार की उस याचिका पर दिया गया जिसमें सजा बढ़ाने की मांग की गई है। तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ से कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था, और उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जाए।

दिल्ली ने हासिल किया 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य

सरकार और जनता की साझेदारी से बदली दिल्ली की हरियाली की तस्वीर: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा-भरा, स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मिशन ग्रीन दिल्ली के तहत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि केवल संख्या पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और स्वच्छ हवा के लिए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। दिल्ली को ऐसा शहर बनाना सरकार का लक्ष्य है, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि मेगा प्लांटेशन ड्राइव-2026 की शुरूआत इस वर्ष 7 जुलाई को वन महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन में इस अभियान को हमारी सरकार ने करीबी निगरानी में दिल्लीभर में आगे बढ़ाया गया। इस अभियान में दिल्ली की हरित एजेंसियों और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ-साथ स्थानीय

निकायों, सार्वजनिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों, आरडब्ल्यूए और दिल्ली के नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की। पूरे सरकारी तंत्र और समाज की सामूहिक भागीदारी ने ह्यमिशन ग्रीन दिल्ली को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जनआंदोलन का स्वरूप दिया।

दिल्ली के रिज क्षेत्रों में करीब 25 लाख पौधरोपण

दिल्ली की पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण मध्य रिज, डीडीए रिज और दक्षिण रिज क्षेत्रों में विशेष रूप से पौधरोपण किया गया। इन रिज क्षेत्रों में कुल 24,94,505 पौधरोपण किए गए। प्राकृतिक हरित क्षेत्रों को मजबूत करना दिल्ली की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र के पुर्नथापन, जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय सुधार को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य हासिल होना यह दिखाता है कि जब सरकार और नागरिक साझेदार के रूप में काम करते हैं तो बड़े पर्यावरणीय लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। प्रत्येक लगाया गया पौधा स्वच्छ हवा, अधिक हरियाली और बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का प्रयास केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस हरित संपदा के संरक्षण और संवर्धन पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाएगा।

जनभागीदारी बनी अभियान की सबसे बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि ह्यमिशन ग्रीन दिल्लीह्ल में आम नागरिकों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया। पब्लिक स्लॉट बुकिंग सुविधा के माध्यम से 1,89,116 बुकिंग की गईं, जिनमें 1,47,095 नागरिकों ने भाग लेकर 3,56,986 पौधे लगाए। इससे पर्यावरण संरक्षण में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ावा मिला। इसी तरह वृक्षरथ पहल के माध्यम से पौधों को सीधे कॉलोनियों और समुदायों तक पहुंचाया गया।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डीयू में प्रदर्शन

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय में क्रांतिकारी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और यौन उत्पीड़न की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा पुलिस की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई गई।

संगठन ने कहा कि हाल के दिनों में बिहार के जमुई में महिला से छेड़छाड़ तथा दिल्ली के कालकाजी में महिला से सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। संगठन के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के आसपास मुखर्जी नगर और विजय नगर में भी महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं। इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और पुलिस की मौजूदगी नहीं होने का आरोप लगाया गया। क्रांतिकारी युवा संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। संगठन ने बताया कि वह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रैलियां आयोजित कर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग को आगे बढ़ाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

एआई मॉर्फ तस्वीरें 24 घंटे में हटाए मेटा, पीड़िता को पुलिस सुरक्षा

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कथित तौर पर एआई के जरिए मॉर्फ की गई तस्वीरों के प्रसार से जुड़े मामले में बड़ा आदेश देते हुए मेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों से सभी आपत्तिजनक तस्वीरें और संबंधित वेबलिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता महिला को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीजेपी से जुड़े अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है।

याचिका में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी तस्वीर को एआई तकनीक की मदद से एडिट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉर्फ किया गया और उसे सोशल मीडिया तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। महिला ने अदालत से इन तस्वीरों और उनसे जुड़े सभी वेबलिंक हटाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इसके बावजूद कथित आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिन्हें हटाने की मांग को लेकर महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया। इससे पहले नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में पीड़िता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने उसे धमकाया, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की और उसकी तस्वीर का एआई के जरिए गलत इस्तेमाल किया। एफआईआर में अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम शामिल हैं। महिला ने यह भी मांग की है कि तस्वीर बनाने, उसे प्रदर्शन में इस्तेमाल करने, वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने और पूरे घटनाक्रम में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच की जाए।

दिल्ली दंगे के आरोपी की जमानत की शर्तों में ढील

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी मीरान हैदर की जमानत की शर्तों में ढील दी और उसे हफ्ते में दो बार के बजाय हर शनिवार को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने को कहा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि चूंकि हैदर की शादी 17 अक्तूबर को होनी है, इसलिए उसे 17 और 24 अक्तूबर को हाजिरी लगाने से छूट दी जाती है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की बाकी शर्तें जैसे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट न करना और किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा न लेना या किसी सभा, रैली या मीटिंग को संबोधित न करना या उसमें शामिल न होना ट्रायल खत्म होने तक वैसी ही रहेंगी।

एक ने गन निकाली, बाकी दो ने चाकू, फिर बारी-बारी से की दरिंदगी

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वह जन्मदिन के दिन दोस्त के साथ मंदिर में पूजा के लिए निकली थी। दर्शन के बाद रास्ते में एक पार्क में तीन लोगों ने उन्हें पकड़ा और गैंगरेप किया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि वह जन्मदिन के अवसर पर कालकाजी मंदिर में पूजा करने के लिए निकली थी और इसकी जानकारी उसने अपनी बहन को दी थी। शाम को मंदिर में पूजा पाठ के बाद वह अपने दोस्त के साथ लौटी और कालकाजी मेट्रो स्टेशन के बाहर से खाने के लिए चिप्स और पानी की बोतल खरीदी। बाद में वे दोनों इस्कॉन मंदिर जाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले खाने-पीने के लिए एक पार्क में चले गए। यहीं तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें पकड़ा।

सूत्रों ने बताया कि अपने बयान में पीड़िता ने कहा है कि पार्क में तीन युवक इसके दोस्त के एक तरफ ले गए, जबकि उसे झाड़ियों की ओर ले जाकर तीनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आपस में बातचीत के दौरान एक लड़के ने कहा, ह्यआसिफ भाई, गन निकाल ह्ल जिस लड़के को आसिफ कहकर बुलाया गया, उसने बैंगनी रंग की शर्ट पहन रखी थी और वह तीनों में सबसे ज्यादा मजबूत शरीर वाला था। आसिफ ने काले रंग की बंदूक निकाली और कुछ देर बाद उसे वापस अपनी जेब में रख लिया।

आरोप है कि इसके बाद दोनों लड़कों ने चाकू निकाल लिए और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। आसिफ ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और लाल रंग की बेंच पर लिटा दिया। इसके बाद उसने दूसरे लड़के से कहा, ह्यहेमू, इधर नजर रखना, कोई इस तरफ न आए ह्ल आसिफ ने गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ जबरदस्ती की। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह रो रही थी। इसके बाद आसिफ ने हेमू से कहा, ह्यहेमू, तुम आओ, मैं दीपु के पास जा रहा हूं ह्ल इसके बाद हेमू उसे पास की दूसरी बेंच पर ले गया। उसने भी उसकी गर्दन पर चाकू रखा और जबरदस्ती की। इसके बाद तीसरा लड़का, जिसे दोनों दीपु नाम से बुला रहे थे, वहां आया। उसने भी उसकी गर्दन पर चाकू रखा और उसके साथ जबरदस्ती की। सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि तीनों लड़कों ने गैंगरेप के बाद उनके मोबाइल फोन वापस किए और किसी अन्य को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी थी। अपने बयान में उसके कहा कि पार्क से बाहर निकलने के बाद उसके दोस्त ने पुलिस को फोन किया था।

दिल्ली पुलिस बैंक कर्मचारी यूनियन को प्रदर्शन के लिए स्थान आवंटित करे: उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुलिस से कहा कि वह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दिल्ली स्टेट को अगले हफ्ते यहां शांतिपूर्ण धरना देने के लिए कोई जगह उपलब्ध कराए।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने पुलिस प्रशासन से कहा कि वह किसी दूसरी जगह पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की इजाजत की मांग वाली यूनियन की अर्जी पर फैसला करे। इससे पहले पुलिस के वकील प्रीतिश सभरवाल ने उच्च न्यायालय से कहा था कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा, उन्हें कुछ दीजिए। वे कह रहे हैं कि उन्हें कोई दूसरी जगह दी जाए। इसके लिए उन्हें अदालत नहीं आना चाहिए। न्यायमूर्ति महाजन ने पुलिस विभाग से कहा कि वह शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के लिए कोई वैकल्पिक जगह देने के बारे में सोमवार तक फैसला करे और याचिकाकर्ता को इसकी जानकारी दे।

प्रतिनिधित्व करता है

अपनी याचिका में, ह्ययूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस दिल्ली स्टेटह्ल ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह केंद्र और दिल्ली पुलिस को उन्हें 28-30 सितंबर को जंतर-मंतर या शहर में किसी अन्य जगह पर शांतिपूर्ण धरना करने की अनुमति देने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह बैंकिंग उद्योग में कर्मचारी संघों का एक मुख्य संगठन है, जो सेवा शर्तों पर बातचीत करने में ज्यादातर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

हड़ताल क घोषणा की है

याचिका में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन ने पहले बैंक कर्मचारियों के आंदोलन को नाकाम करने के लिए 11 और 18 सितंबर को धरना देने की इजाजत मनमाने ढंग से आखिरी समय पर देने से इनकार कर दिया था और अब अगले हफ़्ते प्रदर्शन करने के लिए उनकी नई अजी पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सप्ताह में पांच कार्यदिवस समेत बैंक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठाने की मांग करते हुए 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की है।

अन्य मांगों में पेंशन में सुधार और उसे अद्यतन करना, सभी पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते का एक समान फॉर्मूला और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अपनाने का विकल्प शामिल है।

बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किल बढ़ी, महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 3 अगस्त को बरी कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है।

कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सेशन कोर्ट में अपील की है। मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर के बरी होने के आदेश को भी चुनौती दी गई है। महिला पहलवानों की अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट शनिवार को सुनवाई कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और सबूतों का गलत व चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया है।

अपील में आरोप लगाया गया कि आदेश अनुमान और अटकलों पर आधारित है और स्थापित कानूनी सिद्धांतों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। महिला पहलवानों का कहना है कि आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को महिला पहलवानों द्वारा दी गई चुनौती बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ा सकती है।

कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष हमेशा से महिला पहलवानों द्वारा अपने ऊपर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को गलत बताते रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी किए जाने के बाद उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए बड़ी राहत है। ये उन लोगों के लिए भी बड़ी राहत है, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे आरोप लगने के बाद किसी भी व्यक्ति के परिवार वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं और आदमी टूट जाता है। कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे केस से उन सभी को बल मिलेगा, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं। मेरा केस एक उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा था, मुझ पर आरोप लगाने वाले ओलंपिक मेडलिस्ट थे। इसमें बहुत बड़े लोग शामिल थे। इसमें विपक्ष की बड़ी पार्टियां शामिल थीं। देश और देश के बाहर भी प्रदर्शन हुआ था। मैंने खुद को कभी अपराधी माना ही नहीं।

बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच का ये विवाद देश के सबसे चर्चित खेल और कानूनी विवादों में से एक है। इसकी शुरूआत 2023 में हुई थी। देश की कई नामी महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 से 2022 के बीच बृजभूषण शरण सिंह द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंप, डब्ल्यूएफआई कार्यालय और अन्य स्थानों पर उनके साथ अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न हुआ।

पकड़े गए दो ड्रग तस्कर, 939 ग्राम हेरोइन और 7.93 लाख रुपये कैश बरामद

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। बाहरी-उत्तर जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बवाना की न्यू सनौठ कॉलोनी से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पार्वती (42) और विकास कुमार उर्फ शानू (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 939 ग्राम उच्च गुणवत्ता की हेरोइन, 615 ग्राम पावर-कट पाउडर, 7.93 लाख रुपये नकद और एक टाटा हैरियर बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर को एंटी नारकोटिक्स स्क्वॉड को न्यू सनौठ कॉलोनी में नशीले पदार्थों की सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी।

दिल्ली के मॉडल टाउन में हल्दीराम की दुकान में लगी आग, कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में हल्दीराम की एक दुकान में शुक्रवार को आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 23 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा कि हल्दीराम की दुकान में आग लगने की सूचना अपराह्न 2.23 बजे मिली। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद शुरू में चार गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन अपराह्न साढ़े तीन बजे मौके पर मौजूद टीम ने और वाहनों की मांग की, जिसके बाद 19 और गाड़ियों को भेजा गया।

अधिकारी ने बताया, हमने कुल 23 गाड़ियों को मौके पर भेजा है। उन्होंने बताया कि अपराह्न तीन बजकर 55 मिनट पर आग पर काबू पा लिया गया और शाम चार बजे तक आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र को ठंडा करने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत या जख्मी होने की सूचना नहीं है।

भाजपा नेताओं ने दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि, उनकी वैचारिक विरासत को किया याद

नई दिल्ली, 25 सितंबर (वेब वार्ता)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने शुक्रवार को भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विकास में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने एकात्म मानव के उनके दर्शन और अंत्योदय के सिद्धांत का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ह्लआज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मजयंती है। अगर किसी नेता ने भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक दिशा देने का काम किया, तो वे वही थे। उन्होंने 1951 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के महासचिव के रूप में काम किया और बाद में इसके अध्यक्ष भी बने।

हर्ष मल्होत्रा ने कहा, उन्होंने जो ह्यएकात्म मानव दर्शन दिया आज हमारी भाजपा का मूल्य विचार वही है और एनडीए की जो सरकारें चलती हैं, उसका भी मूल्य विचार यही है कि जो समाज के अंदर सबसे गरीब-पीड़ित शोषित हैं, उसका उत्थान करना। आज पीएम मोदी ने उनके दर्शन को आत्मसात करते हुए जो मोदी की सरकार की 200 से अधिक गरीबकल्याण, जनकल्याण की जो योजनाएं हैं, उसके पीछे का मूल्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो दर्शन है-एकात्म मानववाद और अंत्योदय का है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण से पिछले 12 वर्षों में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के कारण से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के कारण ही भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम आज उनको स्मरण करके उनकी जयंती मना रहे हैं।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 25 सितंबर पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। उनका जन्म ब्रज क्षेत्र में हुआ और जिस तरह ब्रज क्षेत्र के भगवान कृष्ण का पूरी दुनिया में बोलबाला हुआ, उसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की आज पूरी दुनिया समीक्षा भी कर रही है और उस पर ही चलने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में उनके विचार इतने प्रभावी है कि उसमें वैश्विक आतंकवाद का समापन है, ग्लोबल वार्मिंग भी उसमें छुपी हुई है और जब तक अंत्योदय की भावना प्रत्येक देश के अंदर नहीं आएगी तब तक गरीबी समाप्त नहीं हो सकती है। मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाई रास्ते पर कर रहे हैं।

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ह्लपंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे मार्गदर्शक हैं। उनकी जयंती पर मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

...और ऐसा करना जारी रखा है

दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने दीनदयाल उपाध्याय को भाजपा कार्यकताओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया। सूद ने कहा, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी इस (भाजपा) पार्टी में काम करने वाले करोड़ों कार्यकताओं के आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने अपने समग्र मानवतावाद के दर्शन में राष्ट्र की सामूहिक चेतना को चिती के रूप में समझाया और बताया कि कैसे इस सामूहिक चेतना के जागृत होने से राष्ट्र का ह्यविराटह्ल स्वरूप उत्पन्न होता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल से ही सामूहिक चेतना के महत्व के बारे में बात की है और ऐसा करना जारी रखा है।

वाहन ट्रांसफर और डील के फर्जीवाड़े पर कसेगा शिकंजा

अब सिम और आरसी का नाम मैच होने पर ही आएगा ओटीपी

वेब वार्ता, कानपुर। वाहन खरीद-बिक्री और आरटीओ सेवाओं में होने वाले अवैध खेल को रोकने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग (डॉट) के साथ मिलकर एक नई और सख्त व्यवस्था लागू की है।

अब परिवहन पोर्टल पर डीएल बनवाने के लिए मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन सीधे दूरसंचार विभाग के डेटाबेस से किया जाएगा। वही बहुत जल्द वाहन ट्रांसफर, एनओसी या अन्य आरटीओ संबंधी सेवाओं में भी यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

आरआई संतोष कुमार ने बताया कि गलत और अवैध तरीके से वाहनों से जुड़े काम रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदक केवल वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर पाएंगे, जो सिम कार्ड उनके अपने नाम (आधार या मान्य आईडी) पर पंजीकृत होगा।

उन्होंने बताया कि पहले किसी भी सक्रिय मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगाकर वाहन ट्रांसफर का आवेदन कर दिया जाता था, जिससे फजीर्वाड़े की गुंजाइश बनी रहती थी। अब इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए परिवहन पोर्टल को दूरसंचार विभाग के टीएएफसीओपी (टफकॉप) सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आवेदन के समय दूरसंचार विभाग तुरंत जांच करेगा कि सिम धारक और डीएल समेत वाहन विक्रेता/क्रेता एक ही व्यक्ति हैं या नहीं।

अगर वाहन मालिक के डीएल ,आरसी या आधार में दर्ज नाम और सिम कार्ड के ओनरशिप रिकॉर्ड में थोड़ा भी अंतर पाया जाता है, तो सिस्टम ओटीपी जारी ही नहीं करेगा। ओटीपी न मिलने की दशा में आवेदन की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ सकेगी।

वाहन स्वामियों के लिए जरूरी सावधानियां

आरटीओ संबंधी किसी भी काम के लिए केवल उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करें, जो सिम आपके नाम पर जारी हुई हो। यदि आपका सिम कार्ड परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, तो आवेदन से पहले अपने नाम का सिम इस्तेमाल करें या रिकॉर्ड अपडेट कराएं। आरसी में दर्ज नाम की स्पेलिंग और सिम कनेक्शन में दर्ज नाम में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

संक्षिप्तवार्ता

लाइव सर्जरी कर विशेषज्ञो ने छात्रो को सिखाएं गुर

वेब वार्ता, कानपुर

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर के नाक, कान एवं गला रोग विभाग द्वारा आयोजित 43वीं यूपीएओईकॉन के अंतर्गत शुक्रवार को विभिन्न शैक्षणिक सत्रों, विशेषज्ञ व्याख्यानों, इंस्ट्रक्शनल कोर्स तथा लाइव सर्जरी का सफल आयोजन किया गया। कई विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और लाइव सर्जरी के माध्यम से छात्रो को गुर सिखाए।

यूपीएओईकॉन -2026 के दूसरे दिन ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. हरेन्द्र कुमार के साथ विनय ने आघात के कारण होने वाली फेशियल नर्व पाल्सी एवं आधुनिक उपचार के विषय में विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. सतीश जैन ने लाइव सर्जिकल सत्र के दौरान नाक, कान एवं थायरॉइड से संबंधित विभिन्न ऑपरेशन प्रदर्शित किए। इस सत्र में प्लास्टिक एवं पुनर्निर्माण शल्यक्रिया तथा सीएसएफ राइनोरिया की एंडोस्कोपिक सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं का भी प्रदर्शन किया गया।

हाथी से चलें या साइकिल से,जनता विकास को देखती है: भाजपा

वेब वार्ता,देवरिया। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता एस एन सिंह ने शुक्रवार को विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हाथी से चले या साइकिल से जनता अब सवारी नहीं बल्कि सरकार का विकास देखती है।

भाजपा प्रवक्ता श्री सिंह ने अपने जारी बयान में कहा कि हाथी से चलें, घोड़ा से चलें, पैदल चलें, रथ से चलें या साइकिल से चलें, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कट्टा-बम चलाने वाली और अपहरण को उद्योग बनाने वाली पार्टियों का शासन देखा है।अपने बयान में उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि रामकोला कांड,जवाहर बाग मथुरा कांड, मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना पलायन, मऊ, रामपुर, कानपुर, बरेली और बदायूं सहित प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगों से नहीं, विकास से प्रभावित होती है। एक तरफ पहले कट्टा-बम बनते थे।आज योगी आदित्यनाथ के सरकार में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। एक तरफ माफियाराज था, दूसरी तरफ एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने देश की समृद्धि और राष्ट्र की मजबूती के लिए ब्रह्मोस बनाने वाली भाजपा सरकार को चुना है और आगे भी चुनेगी।

आकांक्षात्मक विकासखंडों की प्रगति की डीएम ने की समीक्षा

वेब वार्ता, देवरिया। देवरिया जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के आकांक्षात्मक विकासखंडों गौरी बाजार, लार, बरहज, बनकटा एवं भागलपुर की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा निर्धारित संकेतकों के सापेक्ष उपलब्धियों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आकांक्षात्मक विकासखंडों में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख संकेतकों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित की जाए। जिन संकेतकों में अपेक्षित प्रगति नहीं है, उनमें विशेष कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध सुधार लाया जाए। स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित संकेतकों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, कुपोषण तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराने तथा संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

कुशीनगर के सात पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक से हुए सम्मानित

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर में पुलिस विभाग में सराहनीय और निष्ठावान सेवाओं के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से कुशीनगर के सात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बृहस्पतिवार को एसपी कार्यालय में एसपी केशव कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को पदक प्रदान किए। एसपी ने सम्मानित पुलिसकर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस सेवा में कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी और जनसेवा की भावना का विशेष महत्व है। गृह मंत्रालय की ओर से प्रदान किए गए ये पदक पुलिसकर्मियों की वर्षों की मेहनत और समर्पित सेवा का सम्मान हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करेगा।

कीटनाशक के छिड़काव से किसान की मौत, मेरठ में इलाज के दौरान तोड़ा दम

वेब वार्ता, अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कीटनाशक के जहरीले असर से एक किसान की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में मातम छा गया है। मंडी धनौरा थाना क्षेत्र स्थित जेथल मुस्तकम गांव में बुधवार को खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते समय 50 वर्षीय किसान गजेंद्र जाटव की हालत अचानक बिगड़ गई थी। परिजनों ने उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। शुक्रवार तड़के इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जब परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे, तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक गजेंद्र के परिवार में एक विवाहित बेटा और दो अविवाहित बेटियां हैं।

अमरोहा फार्म हाउस गैंगरेप प्रकरण

वेब वार्ता, अमरोहा। उत्तराखंड के विधायक के फार्म हाउस में हरियाणा की युवती के साथ हुए गैंगरेप और पुलिसकर्मियों की संदिग्ध संलिप्तता के खुलासे के बाद अब इस मामले ने एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है।

हसनपुर सर्किल के रझोहा क्षेत्र के फार्म हाउसों में जारी असामाजिक गतिविधियों, देर रात काले शीशे की लग्जरी गाड़ियों की आवाजाही और कथित कोडवर्ड्स के जरिए संचालित वीआईपी नेटवर्क को लेकर स्थानीय किसानों व आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने तथा अवैध निमार्णों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है।

व्यवस्था स्थापित करना अनिर्वा बताया है

प्रशासन से की गई प्रमुख मांगों में यह बात विशेष रूप से शामिल है कि हसनपुर सर्किल के रझोहा से संबंधित फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर को तुरंत पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके। इसके साथ ही, जांच के दौरान जो भी फार्म हाउस अवैध रूप से निर्मित पाए जाएं या जहां भी असामाजिक गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन पर बिना किसी देरी के कानूनी शिकंजा कसते हुए बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी फार्म हाउसों के लिए क्वीक रिस्पांस व एक स्थायी पुलिस निगरानी व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य बताया गया है।

किसान संगठनों का मानना है कि यदि फार्म हाउसों की आड़ में पनप रहे इस नेटवर्क पर तत्काल कठोर अंकुश नहीं लगाया गया, तो उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी (वनंतरा फार्म हाउस) कांड जैसी दुखद और शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना असंभव हो जाएगा। इसी गंभीर आशंका के मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अमरोहा के पुलिस अधीक्षक को भेजे गए प्रपत्रों के माध्यम से उच्चस्तरीय हस्तक्षेप व न्यायिक जांच की मांग की है। किसान नेता नरेश चौधरी का कहना है कि यह मुद्दा अब केवल किसी एक घटना तक सीमित न रहकर तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के जनसरोकारों से जुड़ चुका है। क्षेत्र के विभिन्न फार्म हाउस 'विशेष सेवाओं' और अवांछित गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहे हैं, जहाँ रात के अंधेरे में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है।

हरदोई में नवागत डीएम राहुल पांडे ने पत्रकारों से किया संवाद

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। नवागत जिलाधिकारी राहुल पांडे ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासन को अन्य स्रोतों के साथ-साथ मीडिया के माध्यम से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिनसे जनसमस्याओं और विभागीय समस्याओं के निस्तारण में मदद मिलती है। शासन की प्राथमिकताएं ही उनकी प्राथमिकताएं हैं और जनहित के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा। आईएएस अधिकारी राहुल पांडे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित विवेकानंद सभागार में पत्रकारों से परिचयात्मक वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराना उनकी प्राथमिकता है।

आगामी चुनावों तथा निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को लेकर पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी। पत्रकारों ने शहर की खराब सड़कों, जलभराव, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं तथा नगर में अतिक्रमण समेत कई समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। इस पर डीएम राहुल पांडे ने कहा कि उन्हें हरदोई आए अभी केवल तीन दिन हुए हैं और वह जिले की व्यवस्थाओं तथा विभिन्न समस्याओं को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यवस्थाओं में बदलाव नजर आएगा।जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करने का भरोसा दिलाया।

हरदोई में नाबालिग प्रेमी युगल की मौत से सनसनी

पेड़ पर लटके मिले दोनों के शव

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम सारंगपुर में शुक्रवार को नाबालिग युवक-युवती के शव पेड़ पर लटके मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शव गांव से करीब 500 मीटर दूर नटल बाग के खेत में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मृतकों की पहचान 16 वर्षीय कन्हैया राजपूत और 14 वर्षीय सविता के रूप में बताई गई है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। दोनों के लापता होने के बाद परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान युवक के सोशल मीडिया स्टेटस से परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। तलाश के दौरान दोनों के शव खेत में मिले।

घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की है तथा मामले में आवश्यक जांच की जा रही है।

दोनों के संबंध और परिवार की कथित असहमति को लेकर गांव में चर्चा है, लेकिन इसकी पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियां स्पष्ट होंगी।

कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी सूर्यकिरण', दिखेगा नजारा मोतिहारी में

वेब वार्ता, कुशीनगर। कुशीनगर जिले में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर शुक्रवार को देश की मशहूर सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम की ऐतिहासिक उड़ान का गवाह बनेगा। भारतीय वायु सेना के नौ हॉक एमके-132 विमान कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर बिहार के मोतिहारी पहुंचेंगे। वहां करीब एक घंटे तक आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाने के बाद सभी विमान कुशीनगर लौटेंगे।

करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले नौ विमानों की सटीक फॉर्मेशन दर्शकों के लिए खास आकर्षण होगी। एयर शो के दौरान विमान आसमान में लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और अन्य जटिल मैन्युवर करते नजर आएंगे। सबसे खास नजारा तब होगा, जब विमानों से निकलने वाली केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं-धाराएं आसमान में तिरंगे का स्वरूप बनाएंगी।

बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में विंग कमांडर तेजसवर सिंह ने एयर शो की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम सामान्य रहने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विमान उड़ान भरेंगे। सूर्यकिरण टीम में कुल 11 विमान हैं लेकिन एरोबेटिक प्रदर्शन में नौ विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में करीब 25 सदस्यीय टीम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सूर्यकिरण टीम देश के अलग-अलग हिस्सों में एयर शो के लिए नजदीकी एयरपोर्ट का चयन करती है।

इसी क्रम में कुशीनगर एयरपोर्ट को बेस बनाकर टीम मोतिहारी में प्रदर्शन करेगी। सूर्यकिरण टीम की सबसे बड़ी खासियत विमानों की सटीक फॉर्मेशन उड़ान है। नौ हॉक एमके-132 विमान एक साथ बेहद कम दूरी पर उड़ान भरते हैं। जटिल मैन्युवर के दौरान कई बार दो विमानों के बीच की दूरी पांच मीटर से भी कम रह जाती है। ऐसे में पायलटों के बीच बेहतरीन तालमेल, अनुशासन और आपसी विश्वास की परीक्षा होती है।

रंगों का नजारा लोगों के लिये यादगार रहेगा

एयर शो युवाओं के लिए भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण, अनुशासन और पेशेवर दक्षता को करीब से देखने का अवसर होगा। खासकर वायु सेना और सशस्त्र बलों में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह प्रदर्शन प्रेरणादायक अनुभव हो सकता है। एक साथ नौ विमानों की सटीक उड़ान और आसमान में तिरंगे के रंगों का नजारा लोगों के लिए यादगार रहेगा। सूर्यकिरण टीम का नेतृत्व एसयू-30 एमकेआई पायलट ग्रुप कैप्टन तेजसवर सिंह कर रहे हैं। टीम के मेडिकल ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदर्श चौधरी बिहार के निवासी हैं। इस दौरान विंग कमांडर एसके शेरोन, स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनिल के. शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल और स्क्वाड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंश मौजूद रहे।

फेसलेस होने के बाद आवेदक काट रहे विभाग के चक्कर

फेसलेस के बावजूद कार्यालय में फेस दिखाना अनिवार्य

वेब वार्ता, कानपुर। शासन द्वारा समूचे प्रदेश में संभागीय परिवहन विभाग (आरटीओ) की सेवाएं फेसलेस यानी की बिना कार्यालय आए अब काम आसानी से होगा ऐसा विश्वास आम जनता को दिलाया गया। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड रही है।

एक पीड़ित जिसने अपनी मोटरसाइकिल का री -रजिस्ट्रेशन के लिए कनिष्ठ बाबू विनीता सिंह को 7 सितम्बर को फाइल जमा की और उन्हें 17 दिनों बाद आरसी दी गई। यानी बाबुओ का खेल बंद नही हुआ है। आम लोगो को आज भी पुराने ढर्रे की तरह फुटबाल बना कर खेला जा रहा है। तो वहीं एआरटीओ प्रशासन अपनी चुप्पी साधें हुई है।

आपको बताते चले कि बीते 14 अगस्त 2026 को शासन द्वारा परिवहन विभाग की कई अन्य सेवाओं को ऑटो अप्रूवल और फेसलेस कर दिया। बावजूद विभाग के बाबू लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा का विषय बने हुए है। इन बाबुओ की कार्यशैली पर कोई भी प्रतिबंध एआरटीओ प्रशासन लगाने में नाकामयाब रहे है। जहां शासन की मंशा पारदर्शिता और आम जनमानस को बेहतर सुविधा प्रदान करने और कार्यालयों के चक्कर से राहत दिलाने की खासी मशक्त कर रहा है तो वहीं विभाग के कुछ बाबू अपनी हूकुमत को बरकरार रखने के लिए शासन की गाइड लाइन और सेवाओं को पूरी तरह से धता बताने में लगे हुए है, जिसका उदाहरण गुरूवार को देखने को मिला। जहां एक पीड़ित अपने वाहन का पुनः पंजीयन को बढ़वाने के लिए 7 सितम्बर,2026 को सारे प्रपत्र जमा कर गया,लेकिन महिला बाबू ने उस काम को 17 दिनो बाद किया और उसे विभाग के चक्कर लगवा दिए।

शासन की नितियों को तमाचा जडते परिवहन विभाग के बाबू

कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है

बाबुओ की यह व्यवस्था साफ दशार्ती है कि विभाग में शासन के दिशा निदेशो की कोई कीमत नही है। जो भी होगा बाबू की मर्जी से ही होगा, जोकि शासन और विभाग के उच्चाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खडा करता है।

कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी सूर्यकिरण': दिखेगा नजारा मोतिहारी में

कुशीनगर जिले में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर शुक्रवार को देश की मशहूर सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम की ऐतिहासिक उड़ान का गवाह बनेगा।

वेब वार्ता, कुशीनगर

भारतीय वायु सेना के नौ हॉक एमके-132 विमान कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर बिहार के मोतिहारी पहुंचेंगे। वहां करीब एक घंटे तक आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाने के बाद सभी विमान कुशीनगर लौटेंगे।

करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले नौ विमानों की सटीक फॉर्मेशन दर्शकों के लिए खास आकर्षण होगी। एयर शो के दौरान विमान आसमान में लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और अन्य जटिल मैन्युवर करते नजर आएंगे। सबसे खास नजारा तब होगा, जब विमानों से निकलने वाली केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं-धाराएं आसमान में तिरंगे का स्वरूप बनाएंगी।

बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में विंग कमांडर तेजसवर सिंह ने एयर शो की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौसम सामान्य रहने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विमान उड़ान भरेंगे। सूर्यकिरण टीम में कुल 11 विमान हैं लेकिन एरोबेटिक प्रदर्शन में नौ विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे ऑपरेशन में करीब 25 सदस्यीय टीम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सूर्यकिरण टीम देश के अलग-अलग हिस्सों में एयर शो के लिए नजदीकी एयरपोर्ट का चयन करती है।

इसी क्रम में कुशीनगर एयरपोर्ट को बेस बनाकर टीम मोतिहारी में प्रदर्शन करेगी। सूर्यकिरण टीम की सबसे बड़ी खासियत विमानों की सटीक फॉर्मेशन उड़ान है। नौ हॉक एमके-132 विमान एक साथ बेहद कम दूरी पर उड़ान भरते हैं। जटिल मैन्युवर के दौरान कई बार दो विमानों के बीच की दूरी पांच मीटर से भी कम रह जाती है। ऐसे में पायलटों के बीच बेहतरीन तालमेल, अनुशासन और आपसी विश्वास की परीक्षा होती है।

...विकसित किया है

एयर शो के दौरान विमानों से केसरिया, सफेद और हरे रंग की धुआं-धाराएं निकलेंगी। इससे आसमान में तिरंगे का स्वरूप नजर आएगा। इसके लिए हॉक एमके-132 विमानों में स्वदेशी तकनीक से विकसित रंगीन स्मोक पॉड्स लगाए गए हैं। इस प्रणाली को भारतीय वायु सेना के बेस रिपेयर डिपो, नासिक ने विकसित किया है।

सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम की स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। टीम देश में 800 से अधिक हवाई प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएई और दुबई समेत कई देशों के अंतरराष्ट्रीय एयर शो में भारतीय वायु सेना का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नौ विमानों के साथ जटिल एरोबेटिक मैन्युवर के लिए टीम की अलग पहचान है।

वेलकम फेम अभिनेता मुश्ताक खान का निधन

मुंबई। हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता मुश्ताक खान का 24 सितंबर को 56 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें खास तौर पर वेलकम, गदरः एक प्रेम कथा, आशिकी, हेरा फेरी और मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में निभाए सहायक और हास्य किरदारों के लिए पहचाना जाता था। उनके निधन की खबर से फिल्म जगत में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मुश्ताक खान पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे और मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर में जन्मे मुश्ताक खान ने थिएटर से अभिनय की शुरूआत की थी। वर्ष 1980 में उन्होंने ह्यअल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है से फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद चार दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्मों और कई टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया।

वर्ष 2007 में आई फिल्म वेलकम में बल्लू के किरदार से उन्हें व्यापक लोकप्रियता मिली। इसके अलावा आशिकी में रफू मास्टर, हम हैं राही प्यार के में भगवती प्रसाद मिश्रा, मुझसे शादी करोगी में चुटकी बाबा और गदरः एक प्रेम कथा में गुल खान के किरदार भी चर्चित रहे। गदर 2, स्त्री और स्त्री 2 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर भिड़ंत, तालिबान लड़ाकों से भिड़ी पाक सेना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें तेज हो गई हैं.

पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में अफगान तालिबान के लड़ाकों ने सीमा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसने और हमला करने का प्रयास किया. इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की. इस सीमा पार गोलीबारी में कई तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है, और देर रात तक दोनों ओर से रुक-रुककर फायरिंग जारी रही.

हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से बढ़ा तनाव

हालिया झड़प से पहले भी दोनों देशों के बीच स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी. पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के भीतर स्थित 10 ठिकानों पर हवाई हमले किए थे.

पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय के अनुसार, यह एयरस्ट्राइक अफगानिस्तान की तरफ से भेजे गए उन ड्रोन हमलों का जवाब थी जिन्हें सीमा पर मार गिराया गया था. इससे पूर्व भी कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी वायुसेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हुए हमले किए थे, जबकि अफगान अधिकारियों ने इन हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की बात कही थी.

दोनों देशों के बीच तनाव

दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से घुसपैठ, सीमा पार से गोलीबारी और ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि पाकिस्तान लगातार अफगान सीमा से आतंकियों के प्रवेश करने और चौकियों पर हमला करने का आरोप लगाता आ रहा है, लेकिन काबुल प्रशासन इन दावों को खारिज करता रहा है. बलूचिस्तान के गुलिस्तान क्षेत्र में हुई इस ताजा घटना के बाद डूरंड रेखा के आसपास के इलाकों में सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है, जबकि अफगान तालिबान की ओर से इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.

फॉर्म में छात्रों के नाम, जन्मतिथि और व्यक्तिगत जानकारी में कोई गलती ना हो

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि छात्रों के नाम, जन्मतिथि और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद जारी होने वाली मार्कशीट में छात्रों की जानकारी सही होना जरूरी है। इसके लिए स्कूलों और पेरेंट्स को कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक कई स्तरों पर रिकॉर्ड जांचने और गलती होने पर उस समय रहते ठीक करने का मौका दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में स्कूलों को कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने और परीक्षा के दौरान जारी होने वाले एडमिट कार्ड तक हर चरण में छात्रों की जानकारी ध्यान से जांची जाएगी। सीबीएसई के मुताबिक छात्रों की डेमोक्रेसी डिटेल सबसे पहले स्कूल के रिकॉर्ड में सही होनी चाहिए। इसमें एडमिशन फॉर्म, स्कॉलर रजिस्टर और एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर शामिल है। स्कूल की ओर से जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में भी यही जानकारी सही दर्ज होनी चाहिए। कक्षा 9 के रजिस्ट्रेशन के समय स्कूल और पेरेंट्स को छात्रों की डिटेल को वेरीफाई और प्रमाणित करना होता है।

बंगाल चुनाव में भाजपा ने खर्चे 287 करोड़

पांच राज्यों में कांग्रेस के कुल खर्च से भी ज्यादा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 286.99 करोड़ रुपए खर्च किए, जो इस साल की शुरूआत में हुए चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस के कुल 248.55 करोड़ रुपए के खर्च से अधिक है। निर्वाचन आयोग को सौंपे गए खर्च संबंधी विवरण में इसकी जानकारी मिली है। बंगाल में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी रही तृणमूल कांग्रेस का खर्च विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सत्ता से हटाकर पहली बार सरकार बनाई। घोषित किए गए 293 सीटों के परिणामों में भाजपा ने 207 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी को 80 सीटें मिलीं। पांच राज्यों (असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी) के चुनावों में भाजपा के कुल 529.38 करोड़ रुपए के खर्च में आधे से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल का रहा। पार्टी ने बंगाल में सामान्य प्रचार पर 217.16 करोड़ रुपए और उम्मीदवारों पर 69.83 करोड़ रुपए खर्च किए।

भाजपा ने बंगाल और केरल के अलावा असम में 96.27 करोड़ रुपए, तमिलनाडु में 51.56 करोड़ रुपए और पुडुचेरी में 11.90 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रदेश में 2011 में सत्ता गंवाने से पहले कई दशकों तक बंगाल पर शासन करने वाली माकपा ने 197 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक सीट जीती। उसकी राज्य इकाई ने उम्मीदवारों पर किए गए खर्च समेत कुल 8.23 करोड़ रुपए के व्यय की जानकारी दी।

कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में 42.08 करोड़ रुपए लगाए

कांग्रेस ने राज्य में हाशिये की ताकत होने के बावजूद 293 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और दो सीटें जीतीं। पार्टी ने बताया कि उसने अपने केंद्रीय मुख्यालय और राज्य इकाई के माध्यम से बंगाल में 42.08 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें 12.96 करोड़ रुपए सामान्य प्रचार और 29.12 करोड़ रुपए उम्मीदवारों तथा उनसे जुड़े खर्चों पर व्यय किए गए।

कॉकरोच पार्टी बोली-मुख्य चुनाव आयुक्त 48 घंटे में इस्तीफा दें

वरना देशभर में आंदोलन करेंगे; वे देशद्रोही, SIR में 13 करोड़ नाम काटे

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। पार्टी ने कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो देशभर में आंदोलन किया जाएगा और इसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे।

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ज्ञानेश कुमार इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। उन्होंने SIR के जरिए देश में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट किए। लोगों से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है।

दीपके ने कहा- लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपनी सरकार चुने। लेकिन जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तब से सरकार यह तय कर रही है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं। दरअसल, बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने रक्फ़ को लेकर पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।

चुनाव आयोग पर सवाल उठाना हार की हताशा का नतीजाः नकवी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग में कथित असहमति को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र की नीयत और नियति दोनों है, जो केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही संभव है, तानाशाही में नहीं हो सकती है।

धमतरी में लगातार बारिश से डैम लबालब, गंगरेल के 10 गेट खुले

धमतरी। जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते प्रमुख जलाशयों में जलभराव तेजी से बढ़ा है। 25 सितंबर 2026 को प्रातः 8 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगरेल जलाशय 98.14 प्रतिशत, मुरुमसिल्ली 100 प्रतिशत, दुधावा 97.21 प्रतिशत तथा सोदूर जलाशय 88.18 प्रतिशत भर चुका है। जलाशयों में लगातार हो रही आवक को देखते हुए जल प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न जलाशयों से पानी नदी में छोड़ा जा रहा है।

गंगरेल जलाशय में 64,117 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है तथा जलाशय के 10 गेट खोलकर 54,950 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें से रुद्री बैराज के माध्यम से 6,000 क्यूसेक पानी नहर में तथा 48,950 क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। जलाशय में पानी की लगातार बढ़ती आवक को देखते हुए जल प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से पानी निकासी की जा रही है।

मुरुमसिल्ली जलाशय में 7,465 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है और जलाशय से 7,286 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। दुधावा जलाशय में 18,724 क्यूसेक पानी की आवक के बीच 16,606 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं सोदूर जलाशय में 16,624 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है तथा 5 गेटों से 16,402 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। जलाशयों में पानी की आवक और जलस्तर की स्थिति को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर पानी छोड़े जाने की मात्रा में और वृद्धि की जा सकती है।

जलाशयों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण महानदी सहित संबंधित नदियों के जलस्तर में वृद्धि तथा बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नदी किनारे बसे सभी गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों और आम नागरिकों से विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अपील की है।

तीन ट्रकों में 18.39 क्विंटल गांजा, सात गिरफ्तार

उदयपुर। राजस्थान में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन ट्रकों से 1839 किलो 670 ग्राम गांजा बरामद किया है।

गुजरात-जूनागढ़ में तेंदुए ने 6 साल की बच्ची को उठाया

जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ जिले में बुधवार रात तेंदुए ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर उसे मार डाला। बच्ची की पहचान प्रिशा सोलंकी के रूप में हुई है। घटना का सीसीटीव्ही वीडियो शुक्रवार को सामने आया है।

घटना मेंदरडा में थोभणभाई कोराट के खेत में हुई। गिर वेस्ट डिविजन के DFO प्रशांत तोमर के मुताबिक, तेंदुए के हमले के बाद बच्ची का शव खेत के पास मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने आसपास 8 पिंजरे लगाए हैं। इलाके में लगातार गश्त कर तेंदुए की तलाश की जा रही है। वन विभाग ने लोगों से रात के समय सावधानी बरतने की अपील की है।

ट्रम्प का व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति को स्टेट डिनर

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर आयोजित किया। डिनर की तैयारी फर्स्ट लेडी मेलानिया देखरेख में की गई।

डिनर की शुरूआत पीले स्क्वैश से बने गाढ़े सूप से हुई। इसमें जंगली मशरूम, हरी जड़ी-बूटियां, कुरकुरे पैनसेटा और हरे प्याज वाला तेल डाला गया था। इसके बाद तिल की परत वाली सी-बास मछली परोसी गई। इसके साथ बोक चॉय, भुना बैंगन और हरी चटनी दी गई। बोक चॉय चीन में खाई जाने वाली सब्जी है, जो छोटी पत्तागोभी जैसी दिखती है।

मिठाई में वनीला क्रीम, खट्टी चेरी और अखरोट से बनी मिठाई के साथ आइसक्रीम परोसी गई। आइसक्रीम में व्हाइट हाउस में तैयार किया गया शहद इस्तेमाल किया गया था।

डिनर के दौरान ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और चीन की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से बेहतर हैं। ट्रम्प ने अपने बीजिंग दौरे को याद करते हुए कहा कि चीन में उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ था, अब अमेरिका भी जिनपिंग को वैसा ही सम्मान देना चाहता है।

इस दौरान ट्रम्प ने जिनपिंग को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बाल्ड ईगल का करीब 3 फीट ऊंचा स्टैच्यू भी तोहफे में दिया। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की आजाद और ऊंची उड़ान भरने वाली भावना का प्रतीक है।

अमेरिका कब करेगा शांति समझौता पर हस्ताक्षर?

संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरानी राष्ट्रपति ने किया खुलासा

तेहरान। अमेरिका ईरान कई महीनों तक संघर्ष के बाद एक बार फिर शांति समझौते के मुहाने पर खड़े हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कई बार शांति समझौते की उम्मीद जता चुके हैं. तमाम धमकियों के बाद ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अंत में ईरान शांति समझौते करेगा ही. इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरान का रुख भी सामने आया है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन ने कहा कि तेहरान चाहता है कि अमेरिका नवंबर की शुरूआत में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले समझौता ज्ञापन पर फिर से हस्ताक्षर करे. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले समझौते पर वापस लौट आएं.

ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि 'हत्याओं' के बावजूद तेहरान अभी भी समझौते का इच्छुक है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयान ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि तेहरान बातचीत के जरिए वाशिंगटन के साथ समझौता करने को तैयार है, भले ही ईरान के सर्वोच्च नेता, वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों की हत्या जैसी घटनाएं हुई हों.

किस आधार पर होगा समझौता?

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पेजेशिकयान ने कहा कि जिस चीज पर चर्चा और बातचीत होती है, वह अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में होती है, और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जो

हमारा हक है, उसी पर बात होती है. उन्होंने आगे कहा कि हमने कभी इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहा और इसी आधार पर, अगर दूसरी पार्टी सहमत होती है, तो हम समझौता करना चाहते हैं. ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है और हमने आपके राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) के साथ समझौता किया था. उन्होंने बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसी आधार पर हम आगे बढ़ने को तैयार हैं और अब भी चाहते हैं.

होर्मुज पर दिया बयान

राष्ट्रपति पेजेशिकयान ने कहा कि उस ढांचे पर सहमति बनी थी. हमने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद नहीं किया था. वह खुला था, बिना किसी कानूनी आधार या ढांचे के. अपने देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हम पर हमला किया. उन्होंने हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे सैन्य कमांडरों और सरकार के लोगों की हत्या की और उन्हें शहीद किया.

फिलिस्तीन ने इजरायल की नीतियों पर जताई चिंता

फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल की नीतियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इजरायल की मौजूदा नीतियां फिलिस्तीनियों के जीवन और अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं. अब्बास ने यह भी कहा कि इन कदमों का असर दो-राज्य समाधान की प्रक्रिया से भी आगे जा रहा है. इसी दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया. जब कई राजनयिक सभा से बाहर जा रहे थे, तब नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करना प्रधानमंत्री के तौर पर उनके लिए लिए गए सबसे आसान फैसलों में से एक था.

वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट, यूपी समेत 5 राज्यों में SSR करा सकता है चुनाव आयोग

नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग अगले महीने यानी अक्टूबर में चुनावी राज्यों के लिए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश जारी कर सकता है.

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं. इन राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि माना जा सकता है. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21 के तहत होने वाली यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि मतदान से पहले मतदाता सूची पूरी तरह से अपडेट और त्रुटिरहित हो.

एसआईआर और एसएसआर के बीच अंतर

मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग करता है.. विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची की बेहद व्यापक और गहराई से जांच की जाती है. इसमें प्रत्येक मतदाता की पात्रता और

विवरणों का घर-घर जाकर विस्तृत सत्यापन होता है, ताकि अयोग्य या फर्जी नामों को सूची से बाहर किया जा सके. इसके विपरीत, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का मुख्य उद्देश्य मौजूदा मतदाता सूची को अद्यतन करना होता है. इसके माध्यम से नए युवा मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, जरूरी सुधार किए जाते हैं और पते में परिवर्तन जैसी सामान्य प्रविष्टियों को संशोधित किया जाता है.

देशव्यापी पुनरीक्षण न होने के कारण

फिलहाल पूरे देश में एक साथ एसएसआर कराने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है. इसका एक प्रमुख कारण देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी एसआईआर का तीसरा चरण है. इसके अलावा देश भर में चल रही जनगणना प्रक्रिया भी एक बड़ी वजह है. जनगणना का पहला चरण इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच निर्धारित था, जबकि दूसरा चरण बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों में जारी है. इन व्यापक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और संसाधनों की व्यस्तता को देखते हुए देशव्यापी पुनरीक्षण के बजाय केवल चुनावी राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

निर्वाचन आयोग में आंतरिक विचार-विमर्श

हाल की रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि आयोग के भीतर देशव्यापी पुनरीक्षण न कराने और एसआईआर के दौरान नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं हुई थीं. आयोग के सदस्यों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर अपनी राय रखे जाने की खबरें आई थीं. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्था में निर्णय लेने से पहले अलग-अलग राय आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है.

शादियों के सीजन से पहले झटका

भोपाल थोक बाजार में उछले दालों के भाव, एक हफ्ते में 10 रुपये महंगी हुई तुवर

भोपाल। त्योहार और शादियों का सीजन शुरू होने से पहले दालों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है।

भोपाल के थोक किराना बाजार में सितंबर 2025 के मुकाबले इस साल सितंबर में तुवर दाल 32 रुपये किलो तक महंगी हो गई है। वहीं उड़द मोगर के भाव में 23 रुपये और चना दाल में 3 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि तुवर में पिछले एक सप्ताह में ही करीब 10 रुपये किलो की तेजी आई है।

इससे आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के अनुसार अच्छे माल की तुवर दाल एक सप्ताह पहले करीब 119 रुपये किलो थी, जो अब बढ़कर 130 रुपये किलो हो गई है। 1 सितंबर को इसका थोक भाव करीब 111 रुपये किलो था।

मसूर और अन्य दालों की रोजाना 100 क्विंटल मांग

मसूर के भाव में भले ही एक साल में सिर्फ 1 रुपये किलो की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसकी बाजार मांग काफी अधिक है। भोपाल में मसूर व अन्य टालें की रोजाना करीब 100 क्विंटन तक मांग रहती है। ऐसे में मांग और उपलब्धता में बदलाव का असर बड़ी मात्रा में कारोबार पर पड़ सकता है।

इंदौर में त्योहार, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में चमकीली पन्नियां और ग्लिटर उड़ाने पर लगा बैन

इंदौर। इंदौर शहर में त्योहार, जुलूस व सार्वजनिक आयोजनों में चमकीली पन्नियां नहीं उड़ाई जा सकेंगी। आयोजन में ग्लिटर या माइलर के उपयोग पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु आदेश जारी किया है। आदेश 22 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

संस्था सरोकार ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस वर्ष हुई कम वर्षा को देखते हुए शहर भर में गणेश पंडाल लगाने वालों से अपने समीप के किसी सार्वजनिक बगीचे में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में महापौर को भी संदेश भेजा गया है। इसके लिए संभागायुक्त से भी संपर्क किया जाएगा।

संस्था का कहना है कि इस नवाचार से शहर को आगामी गर्मियों में संभावित जलसंकट से बचाया जा सकेगा। संस्था के संयोजक राम मूंदड़ा व अशोक डागा ने कहा कि सभी शहरवासी इस बार हुई कम वर्षा से अत्यंत चिंतित हैं। इसके दुष्प्रभाव आने वाली गर्मियों में देखने को मिलेंगे। इसलिए किसी नवाचार को प्रभावी करना होगा।

निगम द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील भी बेअसर साबित हुई है। ऐसे में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाली संस्थाओं पर यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यदि कोई संस्था सहयोग नहीं करे तो आगामी नवरात्र में उसे पंडाल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने विगत एक वर्ष में उपलब्ध कराये है 85 हजार युवाओं को रोजगार और सेवा के अवसर : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खनि निरीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश खनिज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। प्रदेश की धरती से हीरा भी निकलता है। कोयले के मामले में भी प्रदेश समृद्ध हैं।

खनिज महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें पारदर्शिता और दक्षता के साथ कार्य करने वाले प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास में नवनियुक्त 62 खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार ने बीते एक वर्ष में 85 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया है। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर भी उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रत्नगर्भा, वसुंधरा से जुड़कर नवनियुक्त खनि निरीक्षकों का भाग्योदय हो रहा है। आज का दिन इन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके जीवन में नया प्रकाश लाने वाला दिन भी है। नवनियुक्त खनि निरीक्षक शासन से जुड़कर सिर्फ नौकरी ही प्राप्त नहीं कर रहे बल्कि सेवा का एक नया अवसर प्राप्त कर अपनी नई पहचान भी प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवनियुक्त खनि निरीक्षक आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें उनके माता-पिता और परिजन का आशीर्वाद एवं सहयोग भी शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश भी प्रगति के मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी युवाओं को शासकीय सेवा में आने पर कर्मचारी नहीं बल्कि कर्मयोगी मानते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने खनि निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ ही विश्वास पत्र भी सौंपा है। सुशासन और लोक कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हुए ये युवा निश्चित ही सभी के लिए गर्व का कारण बनेंगे।

प्रमुख सचिव खनिज साधन श्री विवेक पोरवाल ने कहा कि प्रदेश में खनिजों से होने वाली आय आठ-नौ हजार करोड़ से बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपए हो गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में 72 खनि निरीक्षकों की नियुक्ति की पहल की गई। नवनियुक्त खनि निरीक्षक प्रदेश के खनिज राजस्व को बढ़ाने का कार्य करेंगे। प्रमुख सचिव श्री पोरवाल ने बताया कि भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से 33 कोयला खनन ब्लॉक आवंटित किए, जिसमें से 8 ब्लॉक में कोयला का उत्पादन शुरू हो गया हैं। छह अन्य कोयला खनन ब्लॉक में उत्पादन प्रारंभ करने के लिए माइन डेवलपमेंट का कार्य प्रारंभ किया गया है। छतरपुर जिले में 2 नए क्षेत्रों में हीरे की खोज के लिए अन्वेषण कार्य चल रहा है।

पन्ना जिले के अंतर्गत एक हीरा ब्लॉक आवंटित किया गया है। स्वर्ण अयस्क की प्रोसेसिंग के लिए सिंगरौली में ग्रीनफील्ड गोल्ड कंसंट्रेट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। सिंगरौली और कटनी में 6 स्वर्ण ब्लॉक नीलाम किए गए हैं। भारत सरकार ने खनन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्यप्रदेश को सम्मानित किया है। नीलामी प्रक्रिया और खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए मध्यप्रदेश ने अग्रणी राज्य की पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनियुक्त खनि निरीक्षकों में से 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और नवनियुक्त खनि निरीक्षकों के साथ छायाचित्र खिंचवाया। कार्यक्रम में नवनियुक्त खनि निरीक्षकों ने कहा कि आज उनके लिए होली और दीपावली जैसा खुशी का दिन है। वे अपने दायित्व को पूरी लगन से पूरा करेंगे।

559 युवाओं को म.प्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी देगी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग

भोपाल। मध्यप्रदेश के युवाओं को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण और अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के अंतर्गत 559 ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पद उपलब्ध कराए गए हैं। डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद रोजगार के अवसर तलाश रहे युवा इस योजना के माध्यम से कंपनी के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्युत गृहों में एक वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

नदियों का संरक्षण और शहरी विकास एक-दूसरे के पूरकः आयुक्त श्री भोंडवे

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने कहा कि शहरों का विकास और नदियों का संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं; नदियां न केवल पर्यावरण और समृद्ध जैव विविधता का आधार हैं, बल्कि हमारी भावी जल सुरक्षा की संवाहिका भी हैं।" नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे गुरुवार को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए), भोपाल में आयोजित ह्यशहर नदी संवाद 2026ह्ल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधुनिक शहरी नियोजन के केंद्र में नदी, उसकी सहायक धाराओं, जलग्रहण क्षेत्र और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिकता के साथ समाहित किया जाना अनिवार्य है।

आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि नदी संरक्षण का दायरा केवल मुख्य प्रवाह तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हैडवॉटर स्ट्रीम्स एवं सूक्ष्म सहायक धाराओं का संवर्धन ही निरंतर जल प्रवाह, भूजल पुनर्भरण तथा जैव विविधता को संबल प्रदान करता है। उन्होंने भोपाल की कालियासोत नदी सहित अन्य जल प्रणालियों के पुनरुद्धार एवं संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन के मध्य अंतर-विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया।

शहर नदी संवाद 2026 के मंच पर प्राकृतिक, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञों सहित शोधकताओं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, कलाकारों और कवियों ने सहभागिता कर अंत:विषयक दृष्टिकोण साझा किए। कार्यक्रम में दक्षिणी विंध्य क्षेत्र से उद्गमित होने वाले मध्य भारतीय वॉटरशेड की हैडवॉटर धाराओं, तटीय क्षेत्रों (राइपेरियन जोन) के संरक्षण तथा अनियंत्रित शहरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस संवाद के माध्यम से भावी शोध प्राथमिकताओं, जन-हितैषी नीति-निर्माण और व्यापक लैंडस्केप फ्रेमवर्क के विकास की दिशा तय की गई।

10 हजार अबॉर्शन किट जब्त, बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची जा रही थीं दवाएं

इंदौर। गुरुवार को औषधि विभाग की टीम ने धारकोठी में एक घर में गोडाउन बनाकर अवैध रूप से भंडारण की गई दवाएं और गर्भपात किट जब्त की। धारकोठी में क्वालिटी फार्मा के पते पर निरीक्षण करने पहुंची टीम को जांच के दौरान मौके पर दुकान संचालित होती नहीं मिली। यहां घर में अवैध रूप से बनाया गया गोडाउन मिला, जहां से करीब 10 हजार गर्भपात किट जब्त की गईं। औषधि विभाग के अधिकारियों के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने गर्भपात की दवाइयों के बिल प्रस्तुत नहीं किए।

इससे स्पष्ट हुआ कि घर में गोडाउन बनाकर दवाओं का बिना लाइसेंस भंडारण किया जा रहा था। विभाग ने स्टाक जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस घर में अवैध रूप से दवाएं मिलीं, वह जावेद खान और अजय सवडतकर के नाम से पाया गया। गोदाम का लाइसेंस और विक्रय रिकॉर्ड नहीं मिला। दोनों लंबे समय से बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाएं बेच रहे थे।

जब्त की गई अवैध गर्भपात किट और सिडेनफिल साइट्रेट दवा की कुल कीमत 52 लाख से अधिक है। विभाग ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई औषधि निरीक्षक योगेश गुप्ता, लोकेश गुप्ता और सारिका अग्रवाल की टीम ने की।

एमवाय में तीन एक्स-रे मशीनों के लिए पत्राचार

एमवाय अस्पताल में एक्स-रे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को जांच के बिना लौटना पड़ रहा है। मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तीन नई डिजिटल एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में एमवाय अधीक्षक ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखा है। प्रत्येक मशीन की अनुमानित लागत डेढ़ करोड़ रुपये के आसपास है। एमवायएच अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने बताया कि एमएलसी मरीजों में एक्स-रे की जरूरत सामान्य मरीजों की तुलना में काफी अधिक होती है। गंभीर दुर्घटना या चोट के मामलों में एक ही मरीज के 20 तक एक्स-रे करने की स्थिति बन जाती है। ऐसे में उपलब्ध मशीनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

अस्पताल में वर्तमान में एक डिजिटल एक्स-रे मशीन खराब है। प्रबंधन ने इसे जल्द शुरू करने के लिए खराब ट्यूब का आर्डर दे दिया है, लेकिन मरीजों की सुविधा के लिए नई मशीनों की तत्काल आवश्यकता है।

विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं विभागों के आय वृद्धि के प्रयास

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए आय अर्जित करने वाले सहयोगी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभागों ने राजस्व में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा वित्त वर्ष के अंतर्गत अर्जित राजस्व आय की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न मदों में अर्जित आय की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्राप्ति के लिये निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विभागों द्वारा आय वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों, नवाचारों और अर्जित उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वित्त वर्ष के अंत तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि अनेक विभागों द्वारा वित्त वर्ष में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

इन क्षेत्रों में अग्रणी है मध्यप्रदेश

बैठक में बताया गया कि वाणिज्य कर, खनिज, आबकारी, परिवहन, वन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में प्रदेश कर संग्रहण में अग्रणी है। विभागों ने आय के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त वर्ष के प्रारंभिक पांच महीनों में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। आयकर फाइल रिटर्न करने के क्षेत्र में देश में, मध्यप्रदेश कभी 14 वें क्रम पर था। इस कार्य में प्रदेश अब पांचवें स्थान पर आ गया है। बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

13 हजार 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के कल्याण के लिए नहीं रखेंगे कोई कमी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के बालक-बालिकाओं को अब छात्रावास में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए यह व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत लगभग डेढ़ दशक में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 13 हजार 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। इन वर्षों में 5 करोड़ से अधिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की छात्राओं से चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, सतना और अशोकनगर के पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में रहने वाली बेटियों से बात की। छात्राओं ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें यह उपयोगी सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी गैस सिलेंडर की व्यवस्था अथवा भोजन के लिए अन्यत्र जाने में समय लगता था और खर्च भी अधिक हो जाता था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को छात्राओं ने आधुनिक मेस सुविधा प्रारंभ करवाने के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रदेश के 106 पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों में 9000 विद्यार्थियों के लिए आधुनिक मेस सुविधा का लोकार्पण किया। इस पर 8 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि व्यय हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कार्य की सराहना करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में छात्रावासों में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। युवा भारत में मध्यप्रदेश सबसे युवा राज्य है, जहां पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को यह महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने विभागीय छात्रावासों के समग्र विकास का संकल्प लिया, जिसे वे पूरा कर रहे हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट के तहत छात्रावासों में आधुनिक किचन और डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की गई है। अब छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपयोगी है, जो अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई के लिए आते हैं।

राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि नियमित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होने से विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति एकाग्र होंगे और ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रदेश में अभी लगभग 9000 पिछड़ा वर्ग छात्रावास सीट्स हैं जिनमें 5200 बालकों और 3800 बालिकाओं के लिए रहने की सीट्स की व्यवस्था की गई है। जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रावासों के प्रारंभ होने के बाद पहली बार विद्यार्थियों के लिए मेस व्यवस्था शुरू हुई है। यह विभाग के कार्यों में एक ऐतिहासिक कदम भी है।

अर्बन चैलेंज फंड की दो दिवसीय कार्यशाला

भोपाल। आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको) के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में नगरीय अधोसंरचना परियोजनाओं में निवेश, वित्तीय संसाधनों के संवर्धन तथा नगरीय कायाकल्प की संभावनाओं पर केंद्रित दो दिवसीय कार्यशाला ह्यअर्बन चैलेंज फंड : निर्णय क्षमता, निवेश तत्परता एवं नगरीय परिवर्तन का शुभारंभ हुआ। 'साइटिस 2.0' के अंतर्गत हडको के मानव बस्ती अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला का आधिकारिक उद्घाटन हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। कार्यशाला में नगरीय वित्त प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्बन चैलेंज फंड, बाजार-आधारित वित्त पोषण, पूंजी बाजार की सहभागिता, सार्वजनिक-निजी भागीदारी ,बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग, परिसंपत्ति मुद्रीकरण तथा लैंड वैल्यू कैप्चर जैसे आधुनिक विषयों पर विषय-विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में पटवारी संघ की कठिनाइयों का समाधान

भोपाल। प्रदेश में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पटवारी संघ द्वारा उठाई गई व्यावहारिक, विधिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों पर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। योजना के क्रियान्वयन को लेकर पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की विभिन्न चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

पटवारी संघ की कठिनाइयों के समाधान के लिए गठित पांच सदस्यीय मंत्री समूह में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य काश्यप, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह तथा सहकारिता एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल रहे।

बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की व्यावहारिक, विधिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को सुना गया। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक समाधान एवं स्पष्टता प्रदान की गई।

योजना के अंतर्गत पूर्व से सक्षम राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से तैयार अधिकार अभिलेखों में दर्ज अधिकारों के आधार पर ही विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन किया जाएगा। विलेख में अधिकार अभिलेख में दर्ज अधिकारों से भिन्न कोई नया अधिकार निर्धारित नहीं किया जाएगा। पटवारी अपने निर्धारित शासकीय दायित्व के अंतर्गत अधिकृत निष्पादक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सक्षम प्रक्रिया से पूर्व में तैयार अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत दायित्व का निर्वहन करने पर पटवारी पर अनावश्यक व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित नहीं किया जाएगा। साथ ही, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा विवादित अभिलेखों के आधार पर विलेख का निष्पादन नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों का निराकरण सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। शासन द्वारा आवश्यक विधिक एवं प्रक्रियात्मक स्पष्टता दिए जाने के बाद पटवारी संघ की योजना से संबंधित प्रमुख व्यावहारिक एवं विधिक आशंकाओं का निराकरण किया गया है।

महत्वपूर्ण ख़बर

भारतीय टेनिस खिलाड़ी परिक्षित पर चार साल का बैन

■ नई दिल्ली। भारतीय टेनिस खिलाड़ी परिक्षित सोमानी पर डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण चार साल का बैन लगाया गया है। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी के इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ने उन्हें प्रतिबंधित पदार्थ ट्रिमेटाजिडाइन पाए जाने के मामले में दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने खाने के दूषित होने की उनकी दलील को खारिज कर दिया।
26 साल के परिक्षित का 31 जुलाई, 2025 को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट के दौरान डोप टेस्ट हुआ था। उनके सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ ट्रिमेटाजिडाइन पाया गया था। इसके बाद उन्हें 23 सितंबर 2025 को प्रोविजनल सस्पेंड किया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि परिक्षित अपने सैंपल में मिले प्रतिबंधित पदार्थ का सोर्स स्थापित नहीं कर सके।

एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटी की ऊंची उड़ान

चंबा की सीमा कुमारी ने भारत की झोली में 16 साल बाद दस हजार मीटर रेस में डाला पदक

चंबा। जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीट और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की उड़नपरी सीमा कुमारी ने इतिहास रच दिया है।

महिलाओं की 10,000 मीटर रेस इवेंट में सीमा ने 32:41:54 सेकंड का समय निकालते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। एशियन गेम्स में यह उनका पहला मेडल है। इसके साथ ही सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर इवेंट में भारत का 16 साल लंबा मेडल का सूखा भी खत्म कर दिया है।

सीमा का यह ऐतिहासिक मेडल सिर्फ ट्रैक पर उनकी तेज रफ्तार का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस साहस, गरीबी और संघर्ष की जीत है, जिसकी शुरूआत हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से नंगे पैर हुई थी। उल्लेखनीय है कि सीमा ने 24 से 28 जून तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनीयर प्रतियोगिता में दस हजार मीटर की दौड 34:28:75 में पूरी कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस शानदार प्रदर्शन के चलते सीमा का चयन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ था। सीमा के कांस्य पदक जीतने की सूचना के बाद भारत सहित चंबा जिला में जश्न का माहौल है। गौर रहे कि सीमा चंबा जिला के रेटा गांव की रहने वाली है। इससे पहले भी सीमा कई स्वर्ण सहित अन्य पदक जीत चुकी है।

धर्मशाला के साई सेंटर में निखरा सीमा का हुनर

धर्मशाला। भारत की उड़नपरी और धर्मशाला के साई केंद्र की धाविका सीमा ने एशियाई गेम्स में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। सीमा की इस उपलब्धि से धर्मशाला स्थित साई केंद्र में भी खुशी का माहौल है। चंबा की रहने वाली सीमा के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के सफर की नींव धर्मशाला के साई केंद्र में ही पड़ी थी। यहां प्रशिक्षण के दौरान उनकी प्रतिभा को एथलेटिक्स कोच केएस पटियाल ने तराशा। कठिन प्रशिक्षण और लगातार मेहनत के दम पर सीमा ने राष्ट्रीय और युवा स्तर की कई प्रतियोगिताओं में पदक अपने नाम किए और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी कायम किए। सीमा के प्रशिक्षक केएस पटियाल ने खुशी जताते हुए कहा कि सीमा ने धर्मशाला में प्रशिक्षण के दौरान जिस मेहनत और अनुशासन का परिचय दिया था, उसका परिणाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाई दे रहा है।

भारतीय कबड्डी टीमों का कमाल, एशियन गेम्स में पुरुषों के बाद महिलाएं भी सेमीफाइनल में पहुंचीं; पदक पक्का

आइची नागोया। मौजूदा चैंपियन भारत की पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने गुरुवार को ग्रुप ए के अपने मुकाबलों में क्रमशः चीनी ताइपे और जापान को हराकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष टीम ने जहां ग्रुप के अपने अंतिम मुकाबले में चीनी ताइपे को 37-21 से हराया, वहीं भारतीय महिला टीम ने मेजबान जापान को 50-25 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम की यह ग्रुप चरण में लगातार चौथी जीत थी। इससे पहले भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया, जापान और बांग्लादेश को हराया था।

इस तरह भारत ने ग्रुप चरण में अपने सभी मुकाबले जीतकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया। भारत ने शुरूआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और हाफ टाइम तक 23-11 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा और इस दौरान 14-10 से आगे रही। भारत ने सफल रेड से 28 अंक, तीन बोनस अंक और ऑलआउट से छह अंक हासिल किए।

मुथूट फिनकॉर्प नया स्पांसर, दो घरेलू सीजन के मिले अधिकार

35 इंटरनेशनल मैचों में पहुंचेगा लोगो

मुंबई। भारतीय क्रिकेट के अगले दो घरेलू सीजन के लिए मुथूट फिनकॉर्प नया टाइटल स्पांसर बन गया है।

कंपनी को भारत में होने वाले इंटरनेशनल और घरेलू मैचों के टाइटल स्पांसरशिप राइट्स 31 मार्च, 2028 तक मिले हैं। इस दौरान करीब 35 घरेलू इंटरनेशनल मैच होंगे। इस स्पांसरशिप को ब्लू मुथूट नाम से पेश किया जाएगा। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, डील की बातचीत 4.85 करोड़ रुपए प्रति मैच के बेस प्राइस पर हुई है। हालांकि बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही बेस प्राइस की स्थिति साफ होगी।

> **दो घरेलू सीजन के मिले अधिकार, 35 इंटरनेशनल मैचों में पहुंचेगा लोगो**

इस दौरान भारत में 10 टेस्ट, 12 वनडे और 13 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। यह डील तुरंत प्रभावी होगी। इसका असर 27 सितंबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में दिखाई देगा।

खास बात यह है कि सीरीज का पहला मैच मुथूट के गृह राज्य केरल में खेला जाएगा। पहला वनडे 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में होगा। 1997 में स्थापित हुई मुथूट फिनकॉर्प, कोच्चि के मुथूट परिवार की कंपनी है। नए टाइटल स्पांसर की घोषणा में देरी हुई थी। इसकी एक वजह अधिकारों के लिए गंभीर बोलीदाताओं की कमी बताई गई। ऊंची बेस कीमत भी इसकी वजह रही।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तीन साल तक रहा स्पांसर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सितंबर, 2023 से अगस्त, 2026 तक बीसीसीआई का टाइटल स्पांसर था। तीन साल की इस डील के तहत बैंक भारत में होने वाले पुरुष और महिला दोनों के इंटरनेशनल और घरेलू मैचों का टाइटल स्पांसर रहा। इसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बीसीसीआई को प्रति मैच 4.2 करोड़ रुपए देता था। अगस्त, 2026 में डील खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने नए टाइटल स्पांसर की तलाश शुरू की।

बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता पर फैसला 4 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा : सैकिया

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम की चयनसमिति के प्रमुख अजीत अगरकर का कार्यकाल अगले माह की शुरूआत में 4 अक्टूबर को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नये बोर्ड अध्यक्ष के लिए किसका चयन होगा। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया का कहना है कि अभी बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और मुख्य चयनकर्ता के पद पर कोई भी फैसला 4 अक्टूबर के बाद ही लिया जाएगा। सैकिया ने कहा, जहां तक अगरकर का सवाल है, उनका कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त हो रहा है और हमारे पास चार अक्टूबर तक इस पर विचार के लिए पर्याप्त समय है कि किसे ये जिम्मेदारी दी जाए। चार अक्टूबर के बाद जो जगह खाली होगी, उस बारे में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी आश्वस्त किया कि बीसीसीआई द्वारा कोई भी निर्णय किए जाने के बाद उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाएगी।

वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार अगरकर की जगह लेने के लिए कुछ प्रमुख नामों पर विचार किया जा रहा है, इसमें पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल और अनुभवी स्पिनर प्रज्ञान ओझा का नाम सबसे ऊपर है। प्रज्ञान अभी चयन समिति के एक वरिष्ठ सदस्य हैं और दक्षिणी क्षेत्र प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास चयन प्रक्रिया का मौजूदा अनुभव है। वहीं, पार्थिव पटेल पश्चिमी क्षेत्र (वेस्ट जोन) से चयन समिति में अपनी जगह बना सकते हैं, जो अजीत अगरकर की विदाई के बाद रिक्त होगी।

भारत के तीन तैराक एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंचे

आइची-नागोया। अनुभवी भारतीय तैराक साजन प्रकाश, ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने शुक्रवार को एशियाई खेलों में अपनी-अपनी स्पधाओं के फाइनल में जगह बनाई। अपने आखिरी एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा की हीट में 2:00.94 का समय निकालकर छठे स्थान के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। ऋषभ दास और उत्कर्ष पाटिल ने पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में जगह पक्की की। दास ने 2:00.53 के समय के साथ हीट में कुल चौथा स्थान हासिल किया, जबकि पाटिल 2:02.13 के समय के साथ नौवें स्थान पर रहे।

कारोबार

भारत सरकार के खाते में नहीं जाएगा पैसा'

यूपीआई पर एमडीआर शुल्क को लेकर सीतारमण ने दी सफाई, और क्या कहा?

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर शुल्क) को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह कोई टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के कोष में नहीं जा रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले यह समझना जरूरी है कि यह सरकार का लगाया हुआ शुल्क नहीं है। उनके मुताबिक, एमडीआर शुल्क एनपीसीआई, एग्रीगेटर, सेवा प्रदाता, पीओएस मशीन उपलब्ध कराने वाले और मर्चेंट बैंक की ओर से लिया जा रहा है।

एमडीआर शुल्क को लेकर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क का भुगतान व्यापारी करेगा। यह पैसा भारत सरकार के पास नहीं जा रहा है और सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसका बोझ ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ग्राहक इसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि इसका भुगतान उपभोक्ता को नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पाए हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एमडीआर शुल्क व्यापारी पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि व्यापारी पहले से ही अन्य कार्डों के लेनदेन पर इस तरह के शुल्क का भुगतान करते हैं और उन मामलों में भी यह शुल्क ग्राहक पर नहीं डाला जाता। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारी अलग-अलग ऑफर या अन्य तरीकों से ग्राहकों को लाभ दे सकते हैं, लेकिन इस शुल्क की व्यवस्था कई अन्य कार्ड भुगतान प्रणालियों में भी लागू है।

विपक्ष पर साधा निशाना

निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दों की तलाश कर रहा है और सरकार पर हमला करने के लिए उसके पास पर्याप्त मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह एनपीसीआई, पेमेंट बैंकों और मर्चेंट बैंकरों के बीच लिया गया पूरी तरह पेशेवर फैसला है। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह फैसला सरकार ने लिया है और अब यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने किसी दबाव में आकर ऐसा किया।

उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने कोविड महामारी और युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना किया है, भारत की संप्रभुता के लिए मजबूती से खड़ी रही है और ग्लोबल साउथ की आवाज उठाती है, क्या वह इस तरह के मामले में दबाव में आ जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सरकार का टैक्स नहीं है। उन्होंने विपक्ष के रुख को मुद्दों को लेकर भटकाव वाला बताया।

बीमा खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर

नई दिल्ली। आपने कभी सोचा है कि आप जो बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, उसका प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण छिपा हुआ कमीशन होता है, जो बीमा कंपनियां बैंक, ब्रोकर और एजेंटों को देती हैं। बीमा नियामक इरडा ने अब इस व्यवस्था को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

कमीशन की सीमा तय करने की तैयारी

नियामक ने कमीशन में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, लाइफ इंश्योरेंस के लिए बैंकों और ब्रोकरों के लिए पहले साल के प्रीमियम का कमीशन, जो कई उत्पादों में 40% से ज्यादा था, उसे घटाकर 5 से 20% के बीच किया जा सकता है। साथ ही, भारी-भरकम शुरूआती भुगतान के बजाय इसे पॉलिसी की अवधि में फैलाने का प्रस्ताव है।

क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

नियामक के आंकड़े बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरों का मुआवजा वास्तविक बिजनेस की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने केवल कमीशन के रूप में 60,800 करोड़ रुपये चुकाए, जो कि 18% की वृद्धि है। जबकि प्रीमियम में बढ़ोतरी महज 6.73 फीसदी ही रही। भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है, लेकिन वैश्विक औसत के मुकाबले यहां बीमा की पहुंच अभी भी काफी कम है। इसी असंतुलन को दूर करने और बाजार को पारदर्शी बनाने के लिए ये नए नियम लाए जा रहे हैं।

शेयर बाजार में लौटी हरियाली; सेंसेक्स 176 अंक मजबूत हुआ, निफ्टी 23100 के पार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में कल की भारी गिरावट के बाद आज 25 सितंबर 2026 को शुरूआती कारोबार में हल्की रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स की ओपनिंग से लेकर बाजार के ताजा हाल और ट्रिगर्स को आसान भाषा में समझें। गुरुवार को बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई थी जिससे निवेशकों के अरबों रुपये डूब गए। लेकिन शुक्रवार सुबह बाजार ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है।

वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और क्रूड ऑयल में मामूली नरमी की वजह से आज दलाल स्ट्रीट ने हरे निशान के साथ शुरूआत की है। सुबह 9 बजकर 29 मिनट पर सेंसेक्स 176.20 (0.23%) अंकों की बढ़त के साथ 73,756.74 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 46.50 अंक मजबूत होकर 23,109.60 (0.20%) के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

भारतीय शेयर बाजार में आज ओपनिंग किस स्तर पर हुई?

गुरुवार की भारी गिरावट के बाद आज घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स की तरह भारतीय इंडेक्स भी सतर्क नजर आए। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 आज सुबह 23,221.80 के स्तर पर खुला। वहीं कल के बंद स्तर (23,063.10) के मुकाबले बाजार में शुरूआत में 100 से अधिक अंकों की बढ़त दर्ज की गई, जिससे शुरूआती कारोबार में निफ्टी 23,050 के ऊपर टिका रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स भी शुरूआती घंटी बजते ही 100 से अधिक अंकों की तेजी के साथ खुला।

फिलहाल बाजार में क्या चल रहा है?

शुरूआती कारोबार में बाजार निचले स्तरों से एक टेक्निकल बाउंस-बैक (सुधार) दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल जहां हर सेक्टर लाल निशान में डूबा था, वहीं आज शुरूआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ट्रेंट जैसी कंपनियां टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होकर बाजार को सहारा दे रही हैं। हालांकि, बाजार में अभी भी ऊपरी स्तरों पर सावधानी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद यह एक शॉर्ट-कवरिंग रैली हो सकती है, लेकिन जब तक निफ्टी 23,200 - 23,300 के मजबूत रेजिस्टेंस जोन को पार करके टिक नहीं जाता, तब तक बिकवाल हावी रह सकते हैं।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड: अमेरिका में 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊंचे स्तरों (लगभग 5.16%) पर बनी हुई है, जो विदेशी निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय बाजार से पैसा निकालने पर मजबूर कर रही है। कल ही ऋक्रर ने 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट बिकवाली की है।

आम निवेशकों को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

आसान शब्दों में कहें तो बाजार अभी एक दोराहे पर खड़ा है। अगर निफ्टी 23,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को नीचे की तरफ तोड़ता है, तो बाजार में पैनिक सेलिंग (घबराहट में बिकवाली) बढ़ सकती है जो इसे 22,700 की तरफ धकेल देगी। वहीं, अगर बाजार आज बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहता है, तो यह आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत होंगे। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे आज वीकली एक्सपायरी के बाद वाले दिन आक्रामक ट्रेडिंग से बचें और केवल मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में ही धीरे-धीरे खरीदारी पर विचार करें।

सोशल मीडिया पर 35% भारतीय सिंगल्स एक्टिव

नई दिल्ली। आज का युवा भले ही चौबीसों घंटे इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिये दुनिया से जुड़ा हो, लेकिन असल जिंदगी में वह गहरे अकेलेपन का शिकार है। मैच ग्रुप और इप्सोस के सर्वे में भारतीय युवाओं को लेकर एक चौंकाने वाला विरोधाभास (कनेक्शन पैराडॉक्स) सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 35% भारतीय सिंगल्स अकेलापन महसूस करते हैं। युवाओं का कहना है कि डिजिटल दुनिया में कदम रखते ही सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं और कम लेकिन मजबूत दोस्त बनाना चाहते हैं। युवाओं ने माना, वे ऑनलाइन तो लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन असल में खुद को अकेला पाते हैं। इसकी बड़ी वजह काम का दबाव और करियर की चिंता है। युवा सामाजिक जीवन से ज्यादा काम व पढ़ाई को तवज्जो दे रहे हैं। 55% युवाओं का कहना है कि दिनभर की भागदौड़ के बाद वे इतने थक जाते हैं कि किसी से मिलने-जुलने की हिम्मत नहीं बचती।

बांदा की केन नदी पत्थरों में करती है रंगीन चित्रकारी

400 साल पहले दुर्लभ शजर पत्थरों की हुई थी खोज

उत्तर प्रदेश के बांदा में सिर्फ केन नदी में ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं, जिसमें कुदरत ने खुद कलाकारी की है। ये खास किस्म के पत्थरों को शजर पत्थर कहा जाता है। शजर का पर्शियन में मतलब पेड़ होता है। इन पत्थरों पर उकरी कलाकारी देखकर लगता है कि जैसे किसी चित्रकार या कलाकार ने किया है। पत्थर पर उकेरी हुई पत्तियां, पेड़ और उनकी अनूठी आकृति देखते ही बनती है। इन पत्थरों की पहचान 400 साल पहले हुई थी। अरब से आए लोगों ने इन पत्थरों की खूबियां समझी और मुगलों के समय इनकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई। इन पत्थरों को ज्वैलरी, डेकोरेटिव सामान पर खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो पत्थर पर ये कुदरती आकृति फंगल के विकास के कारण होती है।

बुंदेलखंड के बांदा जिले की केन नदी प्रदेश की इकलौती और देश की दूसरी नदी है जो पत्थरों में रंगीन चित्रकारी करती है। इस नदी में मिलने वाले दुर्लभ पत्थर बेहद खूबसूरत होते हैं जो अपने भीतर दिखने वाली खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इन पत्थरों को शजर कहा जाता है। फारसी में शजर पेड़ को कहा जाता है। खास बात यह है कि कोई भी दो शजर पत्थर एक जैसे नहीं होते, मतलब हर एक पत्थर में अलग-अलग चित्रकारी। दुनिया भर में शजर पत्थर सिर्फ भारत की दो नदियों केन और नर्मदा में ही पाये जाते हैं। अरब देशों में इस पत्थर को हकीक और भारत में स्फटिक कहते हैं। इन दिनों खरीदे व बेचे जा रहे हैं। मशीन से तराशने के बाद शजर पत्थर में झाडियां, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मानव और नदी की जलधारा के चमकदार रंगीन चित्र उभरते हैं। बांदा के स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में किरणें शजर पत्थरों पर पड़ती हैं तो इन पर आकृतियां उभरती हैं। उनका कहना है कि चांदनी की किरणों जब पत्थर पर पड़ती हैं तो उनके बीच में जो भी आकृति आती है, वह इन पत्थरों पर उभर आती है। वहीं, वैज्ञानिकों का मानना है कि शजर पत्थर पर उभरने वाली आकृति फंगस ग्रोथ है।

शौकीन लोग अंगूठी में जड़वाते हैं

शजर पत्थरों का इस्तेमाल आभूषणों, कलाकृति जैसे ताजमहल, सजावटी सामान व अन्य वस्तुएं जैसे वाल हैंगिंग में लगाने के काम में प्रयोग होता है। मुगलकाल में शजर पत्थरों के इस्तेमाल से बेजोड़ कलाकृतियां बनाई गईं। बांदा और लखनऊ में शजर पत्थर से बने आभूषणों का बड़ा कारोबार होता है। शौकीन लोग इसे अंगूठी में नग के तौर पर भी जड़वाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हस्तशिल्पी द्वारका प्रसाद सोनी बताते हैं कि शजर पत्थर की पहले कटाई और घिसाई होती हैं, जिसके बाद इसे मनचाहे आकर में ढाला जाता है। सोने चांदी में जड़ने के बाद शजर की कीमत और बढ़ जाती है।

400 साल पहले हुई थी खोज

हमेशा से ही केन नदी में मौजूद था, लेकिन 400 साल पहले अरब से आये लोगों ने इसकी पहचान की। वह इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गये थे। इन पत्थरों पर कुदरती रूप से पेड़, पत्ती की आकृति उकेरी थी, जिसके कारण उन्होंने इसका नाम शजर रख दिया।

शजर पत्थर को ब्रिटेन ले गई थीं महारानी विक्टोरिया

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया के लिए दिल्ली दरबार में नुमाइश लगाई गई थी। इसमें रानी विक्टोरिया को शजर पत्थर इतना पंसद आया था वह इसे अपने साथ ब्रिटेन भी ले गई थीं।दुनिया भर में खासकर मुस्लिम देशों में शजर पत्थर की खासी डिमांड है। मुसलमानों के बीच में इस पत्थर का विशेष महत्व है। वह इसे कुदरत का नायाब तोहफा मानते हैं और इस पर कुरान की आयतें लिखवाते हैं। इतना ही नहीं मक्का जाने वाले हजयात्री इस पत्थर को लेकर जाते हैं। व्यापारियों के मुताबिक, ईरान में इसकी मुंहमांगी कीमत मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पत्थर को पहनने से बीमारियां दूर भागती हैं।

पौराणिक मान्यता

पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, केन नदी का पुराना नाम कर्णावती नदी था। बाद में इसे किनिया और फिर कन्या कहा जाने लगा। अब इसे केन नदी कहा जाता है। केन एक कुमारी कन्या है का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है।

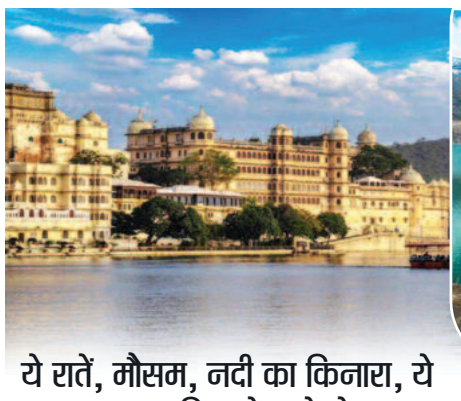

भारत की सबसे सुंदर झील, जिन्हें दुनियाभर से देखने आते हैं लोग

ये रातें, मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा..!! लिखने वाले ने महसूस करने के बाद ही लिखी होंगी ये लाइन। क्योंकि नदी या झील के किनारे पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लेने से मन को जो सुकून मिलता है, शायद ही किसी दूसरी जगह से मिले! अगर आप अपने मन और आंखों को शांति देने के लिए सुंदर और प्रचलित झीलों को देखने का विचार बना रहे हैं, तो यहां पर हम आपको बता रहें हैं भारत की कुछ ऐसी ही बेहद सुंदर झीलों के बारे में, जिनको जानने के बाद शायद आपके कदम खुद को रोक ना पाएं।

पांगोंग त्सो झील, लद्दाख

त्सो यानि झील। लेह से पहाड़ियों के रास्ते महज पांच घंटे की दूरी पर स्थित यह खारे पानी की झील भारत की कुछ अनोखी जगहों में से एक है। आमिर खान और करीना कपूर की हिट फिल्म 'थ्री इडियट्स' के आखिरी सीन की कुछ शूटिंग इसी झील के किनारे हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' एलओसी भी इस झील के जरिए निर्धारित होती है, क्योंकि इस झील का एक बड़ा हिस्सा चीन में आता है। नमक के पानी की होने के बावजूद, सर्दियों में झील पूरी तरह जम जाती है। इस जगह का सुरम्य, मनमोहक और सपनों सा दृश्य आपको एक अद्भुत रोमांच से भर देता है, इसलिए एक बार जाना तो बनता है।

पराशर झील, मंडी, हिमाचल प्रदेश

यह एक बफीर्ली झील है, जो मंडी से 49 किलोमीटर दूर हिमाचली शैली में बने ऋषि पराशर के मंदिर के पास स्थित है। माना तो यह भी जाता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, यह झील तभी से ही बनी हुई है। इस झील का पानी बहता हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसका पानी कहां से आता है और कहां जाता है? आश्चर्य की बात यह भी है कि इस झील की गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका है। सर्दी हो या गर्मी झील का नीले रंग का पानी अलग ही सुकून देता है। प्राक्रतिक सौंदर्य के अतिरिक्त झील में तैरता भूखंड एक आश्चर्य है। झील में तैर रही पृथ्वी के इस बेड़े को स्थानीय भाषा में टाहला कहते हैं। सैलानियों के लिए यह झील बेहद आकर्षण का केन्द्र है।

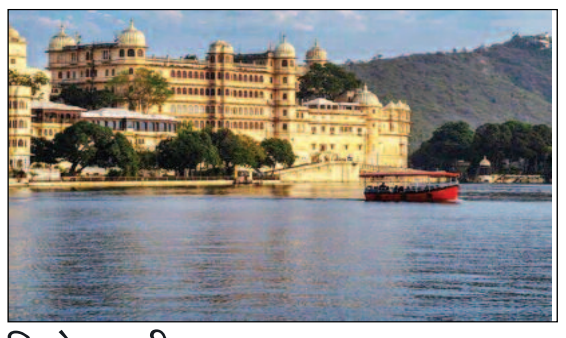

पिछोला झील, उदयपुर, राजस्थान

पिछोला अथवा पिछौला झील राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर की सबसे प्रसिद्ध मीठे पानी की झील है। इस झील के बीचों-बीच जग मंदिर और जग निवास महल है, जिनका प्रतिबिंब झील में पड़ता है। यह एक आर्टिफिशियल यानि मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में एक बंजारे ने करवाया था। जिसे बाद में राजा उदय सिंह ने ठीक करवाया था। सिटी पैलेस से आपको यह पूरी झील दिखाई देती है। रोमांटिक अनुभव के लिए इस झील में आप सूर्यास्त के समय भी सवारी कर सकते हैं।

लोकटक झील, मणिपुर

लोक का अर्थ है 'नदी या झरना' और टक यानि 'अंत'। लोकटक झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। यह झील वनस्पतियों और जीवों की शरण स्थली कही जाती है। इस पर तैरते विशाल हरित घेरों की वजह से इसे तैरती हुई झील भी कहते हैं।

चंद्रताल झील, हिमाचल प्रदेश

सैलानियों और ट्रेकर्स का स्वर्ग कही जाने वाली चंद्रताल झील स्पीति में 4300 मीटर की उंचाई पर स्थित है। यह कुछ बेहद खूबसूरत झीलों में से एक मानी जाती है। इसकी प्राकृतिक छटा का सा नज़ारा शायद ही इस दुनिया में कहीं और देखने को मिले। चंद्रताल झील का यह नाम इसके 'अर्धचंद्राकार' आकार की वजह से ही पड़ा है। चंद्रताल झील पर्यटकों को अपने अलौकिक आकर्षण की वजह से बेहद आकर्षित करती है। साथ ही आकाशगंगा को देखने के लिए स्पीति एकदम सही जगह है। यानि आपकी छुट्टी का पैसा वसूल आनंद।

उमियाम झील, मेघालय

मेघालय के शिलॉन्ग में स्थित उमियाम झील को 'बारा पानी' भी कहते हैं। इस झील का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। वर्तमान में यह झील पूर्वोत्तर भारत के प्रथम हाइडिल पॉवर का हिस्सा है। चारों ओर प्राकृतिक छटा से घिरी यह झील सैलानियों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करती है। फोटोग्राफी और सेल्फी के शौकीनों के लिए यहां के अद्भुत नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य बेहद सटीक है। शायद यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इस झील को देखने आते हैं। इस झील में नौका विहार का आनंद भी लिया जा सकता है।

शिल्लोई झील, नागालैंड

शिल्लोई झील नागालैंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील में एक पवित्र बच्चे की आत्मा वास करती है, इसीलिए ना तो इस झील के पानी का प्रयोग होता है, ना ही इस झील के पानी में मछली पकड़ने या सिंचाई करने जैसा काम होता है। इसीलिए इस झील का पानी बेहद साफ और चमकीला है। यह झील राजधानी कोहिमा से लगभग 285 किमी की दूरी पर है और वीकेंडस पर घूमने के लिए यह बेहद अच्छी जगह है।

चंगु लेक, गंगटोक

इस झील को सोमगो झील, चंगु लेक और त्सोंगमो झील के नाम से जाना जाता है। गंगटोक से 35 किमी दूर नाथूला पास मार्ग पर स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे 'सांगु झील' भी कहते हैं। उंचाई पर स्थित झीलों की बात ही कुछ और होती है। इस झील का सौंदर्य भी कुछ ऐसा ही है। झील में पानी आस-पास की बर्फ पिघलने से आता है। इस झील की एक विशेषता और है, कि भारतीय डाक सेवा ने 2006 में झील को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया था।

वेम्बनाड झील, कुमारकोम, केरल

वेम्बनाड झील अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। यह भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में प्रति वर्ष नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है। प्रतियोगिता में भाग लेने दूर-दूर से प्रतियोगी यहां आते हैं। इतना ही नहीं, यह एक आकर्षक पिकनिक स्थल भी है। वेम्बनाड झील 'बैक वॉटर पर्यटन' के रूप में भी तेजी से विकसित की जा रही है। यहां पर बोटिंग, फिशिंग और साइट सींग सरीखे अनुभवों का आनंद लिया जा सकता है। यानि छुट्टियों का पूरा मज़ा।

डल झील, श्रीनगर

झीलों का जिक्र हो और उसमें डल झील का नाम ना हो? यह तो हो ही नहीं सकता! कश्मीर के प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे डल झील के बिना तो अधूरे ही रहेंगे। इसलिए अगर आप कश्मीर की सुंदरता को पूरी तरह से देखना चाहते हैं, तो आपकी यात्रा में डल झील का नाम अवश्य होना चाहिए। कश्मीर का ताज कही जाने वाली यह झील 18 किमी में फैली और तीन दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। गर्मियों-सर्दियों के दौरान अलग-अलग नज़ारों के साथ बेहद खूबसूरत लगती है। पर्यटक यहां आकर हाउस बोट और शिकारे में बैठकर सूर्योदय का आनंद भी ले सकते हैं। अब और क्या कहें? डल झील और कश्मीर घूमने के लिए भी भला किसी को बहाने की जरूरत होगी?

रोलरकोस्टर जैसा है जापान का ये ब्रिज, इस पर गाड़ी चलाना आसान नहीं

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज जापान का एशिमा ओहाशी ब्रिज दिखने में जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा डरावना इस पर गाड़ी चलाना है। इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। यह ब्रिज नाकाउमी लेक के ऊपर बना है और इस ब्रिज को सीधा बनाने के पीछे कारण है कि जहाज को ब्रिज के नीचे से जाने में दिक्कत न हो। यह ब्रिज साकाइमिनाटो और मात्सू शहरों को जोड़ता है। इस ब्रिज पर गाड़ी चलाना किसी रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं है। यह ब्रिज साल 2004 में बनकर तैयार हुआ था। पहले ऊपर उठना और फिर ढलाने लेते हुए एकदम से नीचे आना आपके रोंगटे खड़े कर देता है।

क्यों बनाना पड़ा ब्रिज का ऐसा डिजाइन

- ये ब्रिज नाकाउमी लेक पर बना है, जो मात्सू और साकाइमिनाटो शहरों को आपस में जोड़ता है।
- ब्रिज को सीधा खड़ा इसलिए बनाया गया है, ताकि लेक में शिप को ब्रिज के नीचे से जाने में दिक्कत न आए।
- दो लेन में क्रांकीट रोड वाला ये ब्रिज 1.7 किमी लंबा है और इसकी चौड़ाई 11.4 मीटर है।
- इसका कंस्ट्रक्शन 1997 में शुरु हुआ और 2004 में पूरा हुआ।
- इस पुल के 6.1 फीसदी झुकाव शिमाने प्रांत की तरह और 5.1 फीसदी झुकाव टोटरी प्रांत की तरफ है।
- अपने अजीबोगरीब डिजाइन के चलते ये पुल रोलरकोस्टर के जैसा नजर आता है।
- ब्रिज की खासियत देखते हुए देहात्सु मोटर कंपनी ने अपनी टांटो मिनीवैन के एड में इसका जिक्र किया है।
- एड में इस पुल के जरिए गाड़ी की स्थिरता की जांच की बात कही गई है।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।